04 - नेपाल में राजनीति की निर्णायक परीक्षा

05 - शिवाजी और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश

A Daily News Magazine
भोपाल
गुरुवार, 19 फरवरी, 2026

06 - 85 दुकानदारों को विस्थापित करने आवंटित किए है भूखंड, बिजली...

07 - मोहन के विजन पर जगदीश की धनवर्षा

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 169, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

सुबह सवेरे

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

शरद की सुबह

हम दौड़ रहे हैं
पर कहाँ के लिए
किसी को नहीं
पता

हम दौड़ रहे हैं
पर किसके लिए
किसी को नहीं
पता

हम दौड़ रहे हैं
जीवन के लिए
या
मौत के लिए
किसी को नहीं
पता

हम दौड़ रहे हैं
घर पाने के लिए
या
घरविहीन होने के लिए
किसी को नहीं
पता

हम दौड़ रहे हैं
बस दौड़ रहे हैं।

-दुर्गाप्रसाद झाला

प्रसंगवश

बांग्लादेश : तारिक और शेख हसीना के बीच कैसे संतुलन साधेगा भारत?

दिलनवाज़ पाशा

अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में बहुत कुछ बदल चुका है। बीएनपी के चेयरमैन और पूर्व प्रधानमंत्री ख़ालिदा ज़िया के बेटे तारिक़ रहमान अब देश के नए प्रधानमंत्री हैं। तेरह फ़रवरी की सुबह जैसे ही बांग्लादेश के चुनावी नतीजों की तस्वीर साफ़ हुई, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक़ रहमान के लिए बधाई संदेश लिखा 'यह जीत बांग्लादेश की जनता के आपके नेतृत्व पर जताए गए भरोसे को दिखाती है।' वहीं, बीएनपी के चेयरमैन तारिक़ रहमान के सलाहकार हुमायूं कबीर ने भी एक बयान में कहा कि बांग्लादेश भारत के साथ अपने रिश्तों को नई दिशा देना चाहता है। हालांकि एक साक्षात्कार में हुमायूं कबीर ने यह भी कहा, 'बदलाव भारत की सोच में आना चाहिए। आज के बांग्लादेश में शेख़ हसीना और अवामी लीग का अस्तित्व नहीं है।'

बांग्लादेश में सत्ता छोड़कर शेख़ हसीना 5 अगस्त 2024 को भारत पहुंची थीं और तब से ही भारत में रह रही हैं। शेख़ हसीना की भारत में मौजूदगी ने दोनों देशों के रिश्तों में जटिलताएं पैदा की हैं। ऐसे में यह अहम हो गया है कि भारत बीएनपी के तारिक़ रहमान और अवामी लीग की नेता शेख़ हसीना के बीच संतुलन कैसे बनाएगा?

विश्लेषक मानते हैं कि भारत के लिए बांग्लादेश की नई सरकार से संबंध मज़बूत करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। शेख़ हसीना इन संबंधों में एक कारण तो ज़रूर होंगी लेकिन उनकी भारत में मौजूदगी भारत-बांग्लादेश के संबंधों के लिए बहुत निर्णायक नहीं होगी। वरिष्ठ पत्रकार और अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार जयंता चौधरी मानते हैं कि शेख़ हसीना घटनाक्रम का भारत और बांग्लादेश के नए रिश्तों पर बहुत असर नहीं होना चाहिए। भारत पहले भी अलग-अलग राजनीतिक नेतृत्व के साथ समानांतर संबंध रखता आया है, चाहे नेपाल में अलग-अलग प्रधानमंत्रियों के साथ हो या पाकिस्तान में अलग-अलग सरकारों के साथ।'

विश्लेषक मान रहे हैं कि भारत अपने हितों का ध्यान रखते हुए तारिक़ रहमान को साधने की कोशिश करेगा। अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार डॉक्टर संजय भारद्वाज कहते हैं, 'भारत की विदेश नीति पिछले कुछ वर्षों में ज्यादा प्रेगमैटिक हुई है। भारत ने यह समझा कि हमें 'गवर्नमेंट ऑफ द डे' के साथ काम करना होगा। यानी जो भी सत्ता में हो, उसके साथ संबंध बनाकर अपने हित सुरक्षित करना ज़रूरी है। इसी संदर्भ में अगर तारिक़ रहमान को जनादेश मिला है और वह प्रधानमंत्री बनते हैं, तो भारत उनके साथ काम करेगा क्योंकि बांग्लादेश भारत के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ोसी है। यह कहना कि भारत सिर्फ़ एक पक्ष के साथ खड़ा रहता है, पूरी तरह सही नहीं है।'

हालांकि, विश्लेषक यह ज़रूर मानते हैं कि शेख़ हसीना ने अपने शासनकाल के दौरान भारत को तरजीह दी और भारत और बांग्लादेश के बीच हर स्तर पर सहयोग को बढ़ाया। शेख़ हसीना के कार्यकाल के दौरान भारत ने बांग्लादेश को लगभग 10 अरब डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट दी और उसके साथ कनेक्टिविटी, एनर्जी, ट्रेड और नॉर्थ-ईस्ट के विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं।

संजय भारद्वाज के अनुसार बांग्लादेश भारत के पूर्वी क्षेत्र की रणनीतिक और आर्थिक स्थिरता में केंद्रीय भूमिका निभाता है। दोनों देशों के बीच इतनी गहरी इंटरडिपेंडेंसी बन चुकी है कि किसी भी सरकार के लिए संबंध तोड़ना या दूरी बनाना व्यवहारिक नहीं है।

वहीं, तारिक़ रहमान की बीएनपी भले ही इस्लाम को लेकर जमात-ए-इस्लामी की तरह कट्टर न हो लेकिन सॉफ़्ट इस्लाम को वह भी बढ़ावा देती रही है। ऐसे में, भारत के सामने यह सवाल ज़रूर होगा कि नए प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान पर कितना भरोसा किया जा सके।

प्रो. संजय भारद्वाज कहते हैं, 'शेख़ हसीना ने भारत की अधिकांश सुरक्षा चिंताओं को संबोधित करने का प्रयास किया और उनके नेतृत्व में भारत-बांग्लादेश संबंधों की एक मजबूत नींव बनी। उनका राजनीतिक नैरेटिव सेकुलर और इंक्लुसिव बंगाली राष्ट्रवाद पर आधारित रहा। इसके विपरीत बीएनपी की फाउंडेशनल आइडियोलॉजी 'सॉफ्ट इस्लाम' के साथ जुड़ी रही है। हालांकि इसे जमात-ए-इस्लामी की तरह रेडिकल इस्लाम नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐतिहासिक रूप से धार्मिक पहचान को राजनीतिक विमर्श में शामिल करने की उसकी प्रवृत्ति रही है।' तारिक़ रहमान के पिता जियाउर रहमान के दौर में बांग्लादेश में संविधान के पांचवें संशोधन के ज़रिए सेकुलरिज्म शब्द हटाकर 'ऑलमाइटी अल्लाह में आस्था' जैसे शब्द जोड़े गए और बंगाली राष्ट्रवाद को 'बांग्लादेशी राष्ट्रवाद' के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया। भारत के सामने यह सवाल बना रहेगा कि तारिक़ रहमान पर कितना भरोसा किया जाए।'

साल 2001 से 2006 के बीच जब बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार थी तब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। प्रो.संजय भारद्वाज कहते हैं, 'उस समय नॉर्थ-ईस्ट के कई इंसर्जेंट ग्रुप्स को बांग्लादेश में पनाह मिलने की बात सामने आई थी और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट संगठनों की गतिविधियां भी बढ़ी थीं।'

बांग्लादेश की नई सरकार भी भारत के साथ रिश्तों को लेकर स्पष्ट संदेश दे रही है। एक साक्षात्कार में तारिक़ रहमान के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा, 'भारत को बांग्लादेश की नई राजनीतिक वास्तविकता को समझते हुए अपनी नीति को उसी अनुसार ढालना होगा। बांग्लादेश की नई सरकार भारत के साथ संतुलित, पारस्परिक सम्मान और आपसी हितों पर आधारित संबंध चाहती है न कि किसी एकतरफ़ा निर्भरता पर।' विश्लेषक यह मान रहे हैं कि बांग्लादेश में नई लोकतांत्रिक सरकार बनने के बाद इसमें बदलाव आ सकता है। विश्लेषक यह भी मान रहे हैं कि तारिक़ रहमान के सामने भी घरेलू स्तर पर यह साबित करने की चुनौती होगी कि वह भारत के प्रभाव में नहीं हैं। विश्लेषकों के मुताबिक़ भारत के छोटे पड़ोसी देशों नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में भारत का मुद्दा कई बार हावी रहता है।

बांग्लादेश में भी किसी नेता पर 'भारत के पास बिक जाने' का आरोप लगना नई बात नहीं होगी। इसलिए तारिक़ रहमान को भी क़दम फूंक-फूंक कर रखने होंगे ताकि घरेलू राजनीति में उनके खिलाफ़ यह नैरेटिव न बन जाए। '

अब सवाल यह भी उठ रहा है कि यदि बांग्लादेश की नई सरकार शेख़ हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करेगी तो भारत क्या करेगा? जयंता चौधरी कहते हैं, 'मुझे नहीं लगता कि भारत शेख़ हसीना को आसानी से वापस भेजेगा और ढाका में भी यह बहुत बड़ा राजनीतिक 'हॉट पोटैटो' होगा। अगर नई सरकार उनके खिलाफ़ कठोर क़दम उठाती है तो देश में अस्थिरता बढ़ सकती है, और अगर कुछ नहीं करती तो भी राजनीतिक जोखिम रहेगा।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

वित्त मंत्री ने 4.38 लाख करोड़ का बजट पेश किया

लाड़ली बहनों के लिए सरकार ने खोला खजाना, 23,882 करोड़ का बजट, आठवीं तक के बच्चों को फ्री दूध, 15,000 शिक्षकों की भर्ती होगी

भोपाल (नप्र)। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश का बजट पेश किया है। बजट 4.38 लाख करोड़ रुपए का है। यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बजट है। बजट में पुरानी योजनाओं के क्रियान्वयन पर ज्यादा जोर दिया गया है। साथ ही प्रदेश की जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया है। सरकार ने पहले से चल रही योजनाओं में कोई कटौती नहीं की है। किस विभाग को कितना फंड मिला है। मध्य प्रदेश का बजट 4.38 लाख करोड़ रुपए का है। कुछ विभागों के बजट में बढ़ोतरी की गई है तो कुछ में कटौती की गई है। ग्रामीण विकास के बजट में भारी बढ़ोतरी हुई है। वहीं, सहकारिता विभाग के बजट में कटौती की गई है।

- **प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा**
- **विधायक निधि नहीं बढ़ाने पर हंगामा**
- **यह मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा बजट**

मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को डॉ. मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 का ये बजट 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपए का है। देवड़ा ने करीब 1 घंटे 30 मिनट का बजट भाषण दिया। लाड़ली बहनों के लिए 23,882 करोड़ के प्रावधान का ऐलान किया। युवाओं के लिए 15 हजार शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया। 8वीं तक के बच्चों को फ्री टेट्रा पैक दूध देने की घोषणा की। प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा।

ये बजट GYANII के स्वरूप में है

उन्होंने कहा- ये बजट GYANII के स्वरूप में है। इसमें गरीब, युवा, अन्नदाता (किसान), नारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियलाइजेशन पर फोकस है। इनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए यानी कुल बजट के बड़े हिस्से का प्रावधान किया गया है।

सिंहस्थ के लिए 3060 करोड़ का विशेष प्रावधान

देवड़ा ने कहा- एमपी में यह पहला रोलिंग बजट है। 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 3060 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है।

नारी कल्याण की विविध योजनाओं के लिए 1 लाख 27 हजार - स्व-सहायता समूह, उज्ज्वला योजना समेत नारी कल्याण की विविध योजनाओं के लिए 1 लाख 27 हजार 555 करोड़ के प्रावधान किए हैं। वर्किंग वूमन के लिए 5700 हॉस्टल बनाए जाएंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 40062 करोड़ रुपए की घोषणा की। दरअसल, 2027 में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं।

छात्रों के लिए भी खुला खजाना

वहीं, बजट में वित्त मंत्री ने छात्रों को भी बहुत कुछ दिया है। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 7 लाख 95 हजार विद्यार्थियों को सहायता दी जा रही है। साथ ही तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सरदार पटेल कोचिंग योजना की शुरुआत हो रही है। इसके अंतर्तत चार हजार विद्यार्थियों को लाभ देने का लक्ष्य है। प्रदेश में 294 सांदीपनि स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं।

आदिवासियों का भी रखा ध्यान

वहीं, जनजातीय कार्य विभाग के बजट 15,015 करोड़ रुपए, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग का बजट 4570 करोड़ रुपए, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का 2,591 करोड़ रुपए, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का 1793 करोड़ रुपए और घुमन्त अर्ध घुमन्त कल्याण विभाग का बजट 55 करोड़ रुपए है।

विधायक निधि नहीं बढ़ाने पर विपक्ष का हंगामा

बजट भाषण के दौरान सदन में कांग्रेस विधायकों ने विधायक निधि बढ़ोतरी नहीं किए जाने के कारण बजट भाषण के दौरान हंगामा किया। बजट भाषण पर सवाल उठाए। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने विधायकों को शांत होकर अपनी सीट पर बैठने के निर्देश दिए। वहीं, कांग्रेस विधायक सरकार पर कर्ज के विरोध में खाली डिब्बे और गुल्लक लेकर विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि राज्य का कर्ज लगातार बढ़ रहा है। विरोध के दौरान कांग्रेस नेताओं ने तख्तियां पकड़ी हुई थीं, जिन पर लिखा था कि कर्ज बजट से ज्यादा है, फिर आप कहते हैं कि सब ठीक है।

किसानों पर भी सरकार का जोर

इस बजट में किसान कल्याण एवं कृषि विभाग के लिए 31,759 करोड़ रुपए का फंड है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के लिए 1863 करोड़ रुपए का बजट है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के लिए 2365 करोड़ रुपए का बजट है। इसके साथ ही सहकारिता विभाग का बजट 1679 करोड़ रुपए हैं। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का बजट 772 करोड़ रुपए है। मछुआ कल्याण और मतस्य विभाग का बजट 413 करोड़ रुपए है।

कृषक उन्नति योजना के लिए 5500 करोड़ रुपए

वहीं, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि स्कूलों को स्मार्ट सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल एरिया के नजदीक हॉस्टल का निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं, 15000 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। सीएम कृषक उन्नति योजना के लिए 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को 337 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके साथ ही आधुनिक पद्धति से गौशालाएं संचालित की जाएंगी।

सामाजिक क्षेत्र और महिलाओं के विकास के लिए बढ़ा बजट

सरकार ने इस बार के बजट में सामाजिक क्षेत्र और महिलाओं के विकास पर बल दिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग का बजट 32,730 करोड़ रुपए है। वहीं, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का बजट 22,363 करोड़ रुपए, आयुष विभाग का बजट 1210 करोड़ रुपए और भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास विभाग का बजट 175 करोड़ रुपए किया गया है।

शिक्षा एवं खेल क्षेत्र में बढ़ा बजट

सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में भी बजट बढ़ाया है। स्कूल शिक्षा विभाग का बजट 36,730, उच्च शिक्षा विभाग का 4,247, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास एवं रोजगार विभाग का बजट 2932 करोड़ रुपए किया है। इसके साथ ही खेल एवं युवा कल्या विभाग का बजट 715 करोड़ रुपए और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का बजट 734 करोड़ रुपए हुआ है।

'ग्यान' से 'ग्यानी' की ओर में एक सधा कदम...

त्वरित टिप्पणी/ मप्र बजट

अजय बोकिल

मप्र की डॉ. मोहन यादव सरकार के तीसरे और बतौर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा छठे बजट का लुब्बो लुआब यह है कि यह सरकार द्वारा बीते साल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की चार श्रेणियों 'ग्यान' (गरीब, युवा, अन्नदाता और नारीशक्ति) के कल्याण और सशक्तिकरण की दिशा में एक और सधा कदम है। फर्क इतना है कि अब इस ग्यान में 'इंडस्ट्री' और 'इंफ्रास्ट्रक्चर' का भी इजाफा हो गया है। यानी जो फोकस पिछले साल तय किया गया था, उसी पर आगे रोशनी डाली गई है। चूंकि मप्र अभी भी एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए मुख्यमंत्री की पहल पर इस बार कृषि और शहरी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। बाजार से लगातार कर्ज उठाते रहने के बाद भी सरकार का दावा है कि राज्य की अर्थ व्यवस्था नियंत्रण में और इस वर्ष का बजट भी राजस्व आधिक्य के समाप्त होगा। राजकोषीय घाटा भी तय सीमा में है। पिछले 'जीरो बेस' बजट था तो इस बार 'रोलिंग बजट' का मॉडल अपनाया गया है।

बुधवार को वित्त मंत्री ने विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों की टोकाटाकी और हंगामे के बीच अपना लगातार तीसरा बजट पेश किया तो उन्हें अहसास था कि विपक्ष शांति से बजट नहीं सुनने वाला। इसलिए अपने डेढ़ घंटे के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने अविचल भाव से आखिर तक बजट भाषण पढ़ा। विभिन्न योजनाओं के लिए उनके बजट आवंटन और कल्याणकारी योजनाओं के ऐलान पर सत्ता पक्ष की ओर से कई बार मेजे थपथपाई गईं तो दूसरी तरफ किसी न किसी मुद्दे पर विपक्षी सदस्य व्यवधान डालते रहे। बजट भाषण के आखिरी दौर में कांग्रेस विधायक नारेबाजी करते हुए गर्भगृह तक जा पहुंचे और वहीं धरना देकर बैठ गए।

उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट के बाद हुई पत्रकार वार्ता में कहा कि यह बजट हमने जनता के सुझावों के आधार पर तैयार किया है और सभी का ध्यान रखने की पूरी कोशिश की है। हमारा एकमात्र उद्देश्य विकसित और आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश बनाना है। यही वजह कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पिछला साल उद्योग वर्ष घोषित किया था तो यह वर्ष किसान कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है।

राजनीतिक दृष्टि से देखें तो मप्र में अगले साल नगरीय निकायों और पंचायतों के चुनाव होने हैं। इसलिए किसानों की आय बढ़ाने, उत्पादन क्षमता में वृद्धि को ध्यान में रखकर कृषि के लिए कुल 1 लाख 15 हजार 13 करोड़ रू. का तथा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 5501 करोड़ रू. का प्रावधान बजट में किया गया है। नगरीय और ग्रामीण विकास पर इस साल बीते साल की तुलना में 22 फीसदी ज्यादा बजट का प्रावधान है। इसी तरह शहरी विकास और ग्रामीण विकास के लिए भी ज्यादा राशि बजट में रखी गई है। चूंकि गृहनगर उज्जैन में सिंहस्थ का सफल आयोजन मुख्यमंत्री मोहन यादव का सपना है, इसलिए सिंहस्थ 2028 के तहत 3060 करोड़ का प्रावधान इस बजट में है।

सरकार ने अधोसरंचना विकास को बजट की धुरी बनाने का दावा किया है। लिहाजा मप्र के इतिहास में पहली बार सड़क, पुल, ऊर्जा, सिंचाई और शहरी सुविधाओं के लिए 1 लाख करोड़ से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। और यह सही भी है कि यह बजट 'समृद्ध मध्यप्रदेश' के विकास को अमली जामा पहनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अगर अधोसंरचना मजबूत होती है तो मप्र में उद्योग धंधे आएंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी ज्यादा बजट का प्रावधान है। लाड़ली बहनाओं के लिए पैसा बढ़ाया भले ही नहीं गया हो, लेकिन जो मिल रहा है, वो मिलता रहेगा। समग्रता में देखें तो वित्त मंत्री का वर्ष 2026 27 का कुल बजट 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रू. कर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11 फीसदी ज्यादा है। सरकार के खर्च बढ़ेंगे, जिन्हें सरकार और कर्ज लेकर पूरा करने की कोशिश करेगी। एसीएस वित्त मनीष रस्तोगी ने कहा कि जीएसडीपी के अनुपात में हमारी कर्ज लेने की क्षमता मान्य सीमा के भीतर ही है। हम जो भी कर्जा ले रहे हैं, वह केवल पूंजीगत कार्यों में ही खर्च हो रहा है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने हमारी सराहना भी है। वैसे भी सरकार द्वारा एक दिन पूर्व सदन में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में मप्र की माली तस्वीर गुलाबी ही दिखाई गई है। बजट में कोई नया कर नहीं है। वैसे भी कराधान और छूट आदि का नियंत्रण अब राज्य सरकार से जीएसटी काउंसिल के हाथों में चला गया है। एक उम्मीद पेट्रोल डीजल पर वेट में राहत की थी, लेकिन उसके बारे में वित्त मंत्री ने कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया।

सरकार ने इस बजट को 'रोलिंग बजट' नाम दिया है। इसका अर्थ वार्षिक बजट को विकास को दीर्घकालिक दृष्टि से जोड़ना है। लिहाजा इस बजट के साथ साथ आगामी दो वर्षों के बजटों के अनुमान भी इसके साथ प्रस्तुत किए गए हैं। यानी सम्बन्धित क्षेत्रों में सरकार अगले दो सालो में कितना खर्च करेगी, यह बताया गया है। सरकार का दावा है कि ऐसा करने वाला मप्र देश में पहला राज्य है। वैसे बजट के साथ विकास की रोलिंग कैसे और कितनी होगी, यह आने वाला वक्त बताएगा।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 20 °c

न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ गुरुवार, 19 फरवरी 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

यूपी में अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा, मायावती का ऐलान

● बीएसपी चीफ ने दिल्ली के बंगला अलॉट पर भी तोड़ी चुप्पी

लखनऊ (एजेंसी)। वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बसपा द्वारा गठबंधन किए जाने के कयासों को बुधवार को पार्टी सुप्रीमो मायावती ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि चुनावी तैयारियों में लगे हमारे नेताओं-कार्यकर्ताओं का ध्यान भटकाने के लिए विरोधियों द्वारा ये साजिश की जा रही है। मीडिया में ऐसी फेक न्यूज प्रसारित कराई जा रही हैं। बसपा वर्ष 2007 की तरह की अकेले अपने बलबूते पर विधानसभा लड़ेगी। बसपा सुप्रीमो ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नौ अक्टूबर को कांशीराम की पुण्यतिथि पर लखनऊ में हुए कार्यक्रम में उन्होंने खुले मंच से अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। इसके बाद कई बार यह बात दोहराई जा चुकी है। अब इस पर चर्चा-बहस की गुंजाइश नहीं है। सभी जानते हैं कि कांग्रेस, सपा और भाजपा की सोच संकीर्ण हैं और ये सभी पार्टियां डा. बीआर आंबेडकर की विरोधी हैं। इनसे गठबंधन में बसपा को हमेशा नुकसान ही होता है।

महाराष्ट्र में अब मुस्लिमों को नहीं मिलेगा आरक्षण

● सरकार ने शिक्षा और नौकरी में 5 फीसदी कोटा खत्म किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। महाराष्ट्र सरकार ने नौकरियों और शिक्षा में मुस्लिमों को मिलने वाला पांच प्रतिशत रिजर्वेशन रद्द कर दिया है। मंगलवार को राज्य के सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक सरकारी रेजोल्यूशन जारी कर पिछले आदेश को कैंसिल कर दिया। पिछली कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने मराठों को 16 प्रतिशत और मुसलमानों को पांच प्रतिशत कोटा देने के लिए एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। हालांकि, पिछले 10 सालों से यह आदेश इनवैलिड था क्योंकि कांग्रेस सरकार की तरफ से लाया गया यह अध्यादेश 6 हफ्ते के बाद विधानसभा से पास नहीं हो सका था। नए आदेश के अनुसार, स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी के तहत शामिल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े मुस्लिम ग्रुप के लिए सरकारी, सेमी-गवर्नमेंट नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पांच परसेंट रिजर्वेशन से जुड़े सभी पिछले फैसले और ऑर्डिनेंस रद्द कर दिए गए हैं। नए आदेश में कहा गया है कि सरकार ने 2014 के पहले के फैसलों और सर्कुलर को रद्द कर दिया है और स्पेशल बैकवर्ड कैटेगरी में मुसलमानों को जाति और नॉन-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट जारी करना बंद कर दिया है। कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने मुस्लिम समुदाय की स्थिति पर कई कमेटियां बनाई।

हिमाचल में ग्रामीणों ने बनाया 'आइस स्केटिंग रिंक'

सरकार 10 साल में नहीं बना सकी, 84 बच्चे ट्रेनिंग ले रहे, नेशनल से एशियन तक चमके

शिमला (एजेंसी)। हिमाचल की राजधानी में एक दशक से ऑल वेदर आइस स्केटिंग रिंक बनाने के सरकारी दावे आज तक कागजों में सीमित हैं, लेकिन शिमला से सटे चियोग के स्थानीय लोगों ने अपने दम पर वह कर दिखाया, जो सरकार नहीं कर सकी। यहां ग्रामीणों ने अपने आराध्य देवता सोगू की जमीन पर पहाड़ी को समतल कर एक शानदार 'आइस स्केटिंग रिंक' तैयार किया है।

अब यहां एक-दो नहीं 84 बच्चे स्केटिंग में अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। इस पहल में ध्यान खींचने वाली बात यह है कि रिंक बिना सरकारी मदद के स्थानीय जागरुक लोगों के सामूहिक प्रयास और जुनून से तैयार हुआ है। ग्रामीणों ने पहले पहाड़ी को समतल किया और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड (30-60 मीटर) का आइस स्केटिंग रिंक बनाया।

चियोग के इस रिंक में दूर-दूर से बच्चे आइस स्केटिंग सीखने पहुंच रहे हैं। स्केटिंग के प्रति बच्चों में ऐसी दीवानगी है कि सुबह छह-सात बजे, जब लोग ठंड के कारण बिस्तर में दुबके होते हैं, उस समय बच्चे यहां अभ्यास कर रहे होते हैं। ट्रेनिंग सुबह 7 से 10 बजे तक स्केटिंग होती है। दोपहर बाद 4 से 6 बजे तक ऑफ-आइस प्रैक्टिस कराई जाती है।

गांव के रिंक से निकल रहे इंटरनेशनल खिलाड़ी

इसी का परिणाम है कि कई बच्चे आज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं। इस रिंक से 14 बच्चे इस साल ओपन नेशनल चैंपियनशिप, 6 बच्चे 'खेलो इंडिया' में भाग ले चुके हैं, जबकि मात्र 8 साल के रुद्रवीर गांगटा एशियन चैम्पियनशिप में मेडल जीत चुके हैं। यह उपलब्धि इस बात का प्रमाण है कि सीमित संसाधनों के बावजूद अगर सही माहौल और मार्गदर्शन मिले, तो गांव के बच्चे भी अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच सकते हैं। शिमला निवासी रुद्रवीर गांगटा ने बताया कि वह एक साल से चियोग रिंक में अभ्यास कर रहे हैं। यहां प्रशिक्षण लेने के बाद उन्होंने नेशनल स्तर पर सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीता, जबकि एशियन चैम्पियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। चियोग निवासी शुभम ठाकुर ने बताया कि वह दो साल से आइस स्केटिंग का अभ्यास कर रहे हैं। वह 'खेलो इंडिया' और एक नेशनल प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं। वहीं नोर्विन ने बताया कि उन्होंने नेशनल गेम्स में भाग लिया है। वह कोच प्रदीप कंवर और रविंद्र से स्केटिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं।

2047 तक भारत को एआई सुपरपावर बनाने का लक्ष्य

● पीएम मोदी बोले-तकनीक का मकसद सबका हित, सबकी खुशी

कहा-इससे रोजगार खत्म नहीं पैदा होगा, युवाओं को दिलाया भरोसा

नई दिल्ली (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत एआई का सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता बनेगा। उन्होंने युवाओं को भरोसा दिलाया कि एआई नौकरियां छीनेगा नहीं, बल्कि नई नौकरी पैदा करेगा। पीएम ने कहा की उनका लक्ष्य 2047 तक भारत को टॉप-3 एआई सुपरपावर बनाना है। दरअसल, नई दिल्ली में 16 फरवरी से दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इवेंट में से एक इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी को इसका औपचारिक उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने एआई को लेकर न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में यह बातें कही हैं।

न्यूज एजेंसी को दिए एक विशेष इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने आईटी उद्योग पर एआई के बढ़ते प्रभाव और सरकार की रणनीति पर बात की। पीएम ने कहा कि भारत का आईटी सेक्टर हमारी इकोनॉमी का मुख्य आधार रहा है। एआई इस क्षेत्र के लिए एक बड़ा अवसर और चुनौती दोनों है। अनुमान है कि 2030 तक भारत का आईटी सेक्टर 400 बिलियन डॉलर (करीब 36 लाख करोड़ रुपए) तक पहुंच सकता है। इसमें एआई आधारित आउटसोर्सिंग और ऑटोमेशन की बड़ी भूमिका होगी। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की थीम पर समि इस समिट की थीम राष्ट्रीय विजन सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय (सभी का कल्याण, सभी का सुख) पर आधारित है। इसका उद्देश्य मानवता के लिए एआई के वैश्विक सिद्धांत को बढ़ावा देना है। समिट में 110 से ज्यादा देश और 30 अंतरराष्ट्रीय संगठन हिस्सा ले रहे हैं। इसमें लगभग 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और 45 से ज्यादा मंत्री शामिल होने पहुंचे हैं। तीन सूत्रों पर टिका है समिट का विजन इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 तीन मुख्य स्तंभों (सूत्रों) पर आधारित है - पीपल (लोग), प्लैनेट (ग्रह) और प्रोग्रेस (प्रगति)। एआई समिट में शामिल होने के लिए आए गूगल सीईओ सुंदर पिचाई ने पीएम मोदी से मुलाकात की।

अपराधी की सजा घटाकर मुआवजा बढ़ाना खतरनाक ट्रेंड

● सुप्रीम कोर्ट बोला-आरोपी पैसा देकर बच नहीं सकते हैं, मदुरै हाईकोर्ट का फैसला रद्द

नई दिल्ली/चेन्नई (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर अपराधों में किसी की सजा घटाकर मुआवजा बढ़ाने को खतरनाक ट्रेंड बताया। मदुरै हाईकोर्ट के एक फैसले पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि इससे समाज में गलत संदेश जाता है कि आरोपी सिर्फ पैसा देकर अपनी जिम्मेदारी से बच सकते हैं। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने कहा कि सजा का उद्देश्य अपराध के प्रति डर पैदा करना है, ताकि भविष्य में अपराध रोके जा सकें। सजा न तो अत्यधिक कठोर होनी चाहिए और न इतनी नरम कि उसका भय खत्म हो जाए। दरअसल, सुप्रीण कोर्ट मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के एक फैसले के खिलाफ दायर हुई याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

आरोपियों को चार हफ्ते में सरेंडर का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए ट्रायल कोर्ट की तीन साल की सजा बहाल कर दी। साथ ही निर्देश दिया कि आरोपी चार सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करें और शेष सजा काटें। ट्रायल कोर्ट को पहले से काटी गई अवधि का समायोजन करने के निर्देश भी दिए गए।

राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति

● केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का कांग्रेस पर बड़ा वार, जमकर घेरा

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने राहुल गांधी को भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति करार दिया। रिजिजू का आरोप है कि राहुल गांधी देश विरोधी ताकतों से जुड़े हुए हैं और वे माओवादियों, उग्रवादियों से मिलते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने कभी ऐसा विपक्ष का नेता नहीं देखा। यह बयान राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा रहा है, क्योंकि यह सीधे राहुल गांधी की छवि पर हमला है। रिजिजू ने आगे कहा, राहुल गांधी भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति बन गए हैं। क्योंकि वे देश विरोधी ताकतों से जुड़े हैं। वे विदेशों में और देश में नक्सलियों, उग्रवादियों, विचारधारावादियों और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों से मिलते हैं। रिजिजू ने संसद के हालिया सत्र में हुए हंगामे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि संसदीय लोकतंत्र में शोर-शराबा और हंगामा हमेशा होता है, हर पार्टी अपना एजेंडा आगे बढ़ाती है।

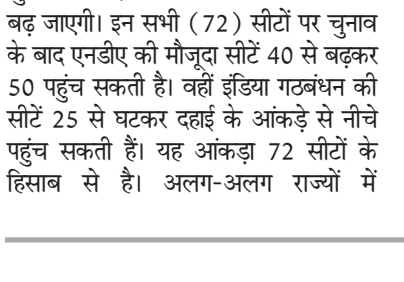

बिहार सरकार ने अपने बुजुर्गों को दी बड़ी राहत

1 अप्रैल से घर बैठे होगी जमीन की रजिस्ट्री, आसान हुई प्रक्रिया

पटना (एजेंसी)। अगर आप कोई जमीन किसी बुजुर्ग से खरीद रहे हैं तो अवर निबंधक सह विशेष विवाह पदाधिकारी द्वारा बुजुर्ग के घर जाकर सत्यापन करेंगे। बुजुर्गों को कार्यालय के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। बस इसके लिए बुजुर्गों को ई-निबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके लिए तय शुल्क 400 रुपये जमा करना होगा। पोर्टल पर उम्र की सीमा 80 वर्ष डालते ही घर और कार्यालय से रजिस्ट्री कराना चाहते हैं इसका ऑप्शन मिलेगा। आप जहां से रजिस्ट्री करने के इच्छुक है वहां के ऑप्शन पर टीक करना है। फिर रजिस्ट्री की तारीख और समय मिलेगा। निबंधन कार्यालय के अधिकारी तय समय के अनुसार आपके घर मोबाइल रजिस्ट्रेशन यूनिट लेकर जाएंगे। फिर आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्री हो जाएगी। इसके लिए ई-निबंधन पोर्टल में बदलाव हो रहा है। ई-निबंधन पोर्टल के सॉफ्टवेयर में बुजुर्गों के घर से रजिस्ट्री करने का ऑप्शन अपडेट करने का कार्य फरवरी में पूरा होगा। इसके साथ ही ट्रायल शुरू हो जाएगा। पूरी व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू करने की योजना है। इससे पहले सभी निबंधन कार्यालयों को लैपटॉप, बायोमैट्रिक आधार वेरिफिकेशन मशीन सहित अन्य सामग्री उपलब्ध कराई गई है।

पाकिस्तान के खिलाफ फिर ऐक्शन की तैयारी में भारत

● पहले सिंधु जल समझौता फिर ऑपरेशन सिंदूर और अब रावी की बारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ पहले सिंधु जल समझौते को रद किया, फिर ऑपरेशन सिंदूर करके उसे गहरा घाव दिया और अब एक और बड़ा कदम उठाने की तैयारी चल रही है। गर्मियां आने वाली हैं ऐसे में पाकिस्तान की पानी की दिक्कतें और बढ़ सकती हैं क्योंकि भारत रावी से पाकिस्तान को सरप्लस पानी का फ्लो रोकने का प्लान बना रहा है। जम्मू-कश्मीर के मंत्री जावेद अहमद राणा के अनुसार, सिंधु जल संधि के सस्पेंशन से पंजाब-जम्मू और कश्मीर बॉर्डर पर शाहपुर कंडी डैम के काम में तेजी आई है और यह प्रोजेक्ट लगभग पूरा होने वाला है। मंत्री ने कहा कि एक बार डैम चालू हो जाने पर भारत रावी नदी पानी रोक देगा।

ममता सरकार-ईडी केंद्र का हथियार एजेंसी बोली-हमें बंगाल में धमकाया

एससी बोला-हम तय करेंगे कौन हथियार और किसे धमकाया गया

नई दिल्ली/कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में आई-पैक से जुड़े रेड मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान ममता सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय का उन राज्यों में हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जहां विपक्ष की सरकार है। वहीं केंद्रीय एजेंसी ने पलटवार करते हुए कहा कि हम किसी के हथियार नहीं हैं। बंगाल में ममता सरकार ने हमें धमकाया। दोनों पक्षों के बीच बहस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसका हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और किसे धमकाया जा रहा है, यह हम तय करेंगे। ईडी ने आई-पैक रेड मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराने की मांग की है।

आई-पैक रेड मामला-2,742 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग केस

आई-पैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी है। यह राजनीतिक दलों के लिए बड़े स्तर पर चुनावी अभियानों का काम करती है। कंपनी और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन पर करोड़ों रुपए के कोयला चोरी घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। एजेंसी ने इस मामले में 27 नवंबर 2020 को एफआईआर दर्ज की थी। पूरा मामला 2,742 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। आरोप है कि 20 करोड़ हवाला के जरिए आई-पैक तक ट्रांसफर हुए। ईडी ने 28 नवंबर 2020 को इसकी जांच शुरू की थी।

राज्यसभा चुनाव का हो गया ऐलान, 16 को वोटिंग

17 राज्यों से कांग्रेस गायब

नई दिल्ली (एजेंसी)। 10 राज्यों की खाली होने जा रही 37 राज्यसभा सीटों को भरने के लिए चुनाव तारीख का ऐलान चुनाव आयोग ने बुधवार कर दिया। 16 मार्च को इन सीटों के लिए वोटिंग होगी। इस साल 245 सदस्यीय राज्यसभा की 72 सीटों पर चुनाव होंगे। पहले 37 और फिर बाकी खाली होने वाली सीटों पर वोटिंग होगी। खाली सीटों पर चुनाव के बाद बीजेपी की ताकत राज्यसभा में बढ़ जाएगी। इन सभी (72) सीटों पर चुनाव के बाद एनडीए की मौजूदा सीटें 40 से बढ़कर 50 पहुंच सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन की सीटें 25 से घटकर दहाई के आंकड़े से नीचे पहुंच सकती हैं। यह आंकड़ा 72 सीटों के हिसाब से है। अलग-अलग राज्यों में विधानसभा की सीटों की संख्या को देखते हुए बीजेपी को 37 से 38 सीटें मिलने की पूरी संभावना है, हालांकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह अपने सहयोगियों के लिए कितनी सीटें छोड़ती है। ये सीट महाराष्ट्र (सात सीट), ओडिशा (चार सीट), तेलंगाना (दो सीट), तमिलनाडु (छह सीट), छत्तीसगढ़ (दो सीट), पश्चिम बंगाल (पांच सीट), असम (तीन सीट), हरियाणा (दो सीट), हिमाचल प्रदेश (एक सीट) और बिहार (पांच सीट) राज्यसभा में खाली हो रही हैं। जिन सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनमें शरद पवार (राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार), अभिषेक सिंघवी (कांग्रेस), हरिवंश नारायण सिंह (जेडीयू,राज्यसभा उपसभापति) साकेत गोखले (तृणमूल कांग्रेस), रामदास अठावले (रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया-अठावले), एम थंबीदुरई (ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम) और तिरुची शिवा (द्रविड़ मुनेत्र कषगम), प्रियंका चतुर्वेदी (शिवसेना उद्धव गुट) शामिल हैं। **बीजेपी की राज्यसभा में बढ़ेगी ताकत-** इस साल खाली हो रही 72 सीटों पर चुनाव के बाद बीजेपी की स्थिति राज्यसभा में मजबूत होगी वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की स्थिति और भी कमजोर होगी। अलग-अलग राज्यों की स्थिति देखें तो कांग्रेस और उसके सहयोगियों की दिक्कत बढ़ेगी। सभी सीटों पर चुनाव के बाद राज्यसभा का अंकगणित बहुत ज्यादा नहीं बदलेगा लेकिन बीजेपी की स्थिति मजबूत होगी। अभी बीजेपी के राज्यसभा में 103 सांसद हैं और एनडीए के 126 सांसद हैं। बीजेपी के 30 सांसदों का कार्यकाल पूरा होगा और 32 सांसदों का आना बिल्कुल तय है।

बीजेपी करेगी कमाल

17 राज्यों से कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं होगा

इस साल खाली हो रही सीटों पर चुनाव के बाद 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से राज्यसभा में कांग्रेस का कोई सदस्य नहीं होगा। इस साल राज्यसभा में कांग्रेस को कुछ सीटें गंवानी पड़ सकती हैं, लेकिन संभावना है कि वह नौ सीटें बरकरार रखेगी। कर्नाटक से तीन, तेलंगाना से दो, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से एक-एक सीट कांग्रेस के खाते में जाने की संभावना है। राज्यसभा में इस साल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, दिग्विजय सिंह और शक्ति सिंह गोहिल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। एक अन्य नेता का कार्यकाल भी पूरा होगा।

मध्यप्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने में मील का पत्थर सिद्ध होगा जन कल्याणकारी बजट : शुक्ल

उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट 'समृद्ध मध्यप्रदेश@2047' की दिशा में दूरदर्शी, समावेशी एवं परिणामोन्मुखी है। उन्होंने कहा कि बजट में 'ज्ञान' (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) से आगे बढ़कर 'ज्ञानी' की अवधारणा को साकार किया गया है, जिसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त रूप से जोड़ा गया है। उन्होंने

कहा कि बजट में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, अधोसंरचना विकास सभी सेक्टर के लिए प्रावधान किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने सर्वस्पर्शी, समावेशी बजट के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित एवं समृद्ध मध्यप्रदेश के निर्माण का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है।

उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। वर्ष 2026-27 के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में कुल 23 हजार 747 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है, जो प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ एवं किफायती उपचार उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत 4600 करोड़ रुपये, चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालयों के लिए 3056 करोड़ रुपये, जिला एवं सिविल अस्पतालों हेतु 2049 करोड़ रुपये तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन हेतु 1934 करोड़ रुपये का प्रावधान स्वास्थ्य तंत्र को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के लिए 1277 करोड़ रुपये तथा राज्यांश सहित कुल 2139 करोड़ रुपये का प्रावधान यह सुनिश्चित करेगा कि गरीब एवं वंचित वर्ग को निःशुल्क उपचार की सुविधा निरंतर मिलती रहे।

मप्र के नगरों के युगांतकारी परिवर्तन और आधुनिक अधोसंरचना का मार्ग प्रशस्त करेगा यह बजट : मंत्री विजयवर्गीय

नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने विधानसभा में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का स्वागत करते हुए इसे प्रदेश के शहरी परिदृश्य में अभूतपूर्व परिवर्तन लाने वाला एक दूरदर्शी रोडमैप बताया है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मध्यप्रदेश के नगरों के सुनियोजित विकास हेतु पूर्णतः संकल्पित है, जिसकी स्पष्ट झलक विभागीय बजट प्रावधानों में परिलक्षित होती है। यह बजट न केवल नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की गुणवत्ता को संवर्धित करेगा, बल्कि विकास की उपलब्धता को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाकर नागरिकों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करेगा।मंत्री श्री विजयवर्गीय ने कहा कि आगामी सिंहस्थ-2028 को वैश्विक भव्यता और दिव्यता प्रदान करने के लिए बजट में 3060 करोड़ रूपये का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक पर्यटन के प्रति शासन की अटूट आस्था को दर्शाता है। नगरीय निकायों को वित्तीय रूप से स्वावलंबी और प्रशासनिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रवेश कर के हस्तांतरण हेतु 3600 करोड़ रूपये तथा 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप स्थानीय निकायों हेतु 2057 करोड़ रूपये के अनुदान का प्रावधान किया गया है, जिससे स्थानीय स्वशासन की नींव और अधिक सुदृढ़ होगी।

प्रदेश के विकास और सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित है बजट : ऊर्जा मंत्री तोमर

ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा आज विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट तथा आगमी 02 वित्तीय वर्षो क्रमशः वर्ष 2027-28 एवं वर्ष 2028-29 हेतु रोलिंग बजट प्रस्तुत किया गया। बजट प्रदेश के विकास और सर्वहारा वर्ग के कल्याण के लिए

समर्पित है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में बनाये गये इस बजट में गरीब, युवाओं, अन्नदाता और नारी सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। ऊर्जा विभाग के लिए इस वर्ष 2026-27 में 33 हजार 606 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इससे बिजली उपभोक्ताओं को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराने में सहूलियत होगी। ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने बताया कि वर्ष 2026-27 के लिये अटल गृह ज्योति योजना के लिए 6033 करोड़ रूपये और अटल कृषि ज्योति योजना के लिए 13914 करोड़ रूपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। आर.डी.एस.एस. योजना के लिए 1091 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। ट्रांसमिशन एवं वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 700 करोड़ रूपये एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के 5 एच.पी. पंपों के लिये निःशुल्क बिजली देने के लिए 5276 करोड़ रूपये की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

बजट पर इनका क्या कहना है

बजट 2026-27 'समृद्ध मध्यप्रदेश 2047' के लक्ष्य की प्राप्ति में सशक्त कदम : राज्यमंत्री पटेल

भोपाल (नप्र)। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को दूरदर्शी, समावेशी और जनकल्याणकारी बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण के साथ औद्योगिकीकरण और अधोसंरचना विकास को गति देने वाला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सशक्त, नेतृत्व में यह बजट 'समृद्ध मध्यप्रदेश ञ2047' के लक्ष्य की प्राप्ति में यह सशक्त कदम है। उन्होंने सर्वस्पर्शी भविष्योन्मुख बजट के लिए उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा का आभार व्यक्त किया है।

अमृतकाल 2047 के लिए विकास का पैमाना है राज्य सरकार का यह बजट

समृद्ध, सुखद और सम्पन्न मध्यप्रदेश के सपने को पूरा करेगा बजट 2026-27 : मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश बना रोलिंग बजट प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ज्ञान आधारित विकास के संकल्प के साथ मध्यप्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है। गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के कल्याण के ज्ञान के संकल्प में हमारी सरकार ने अब इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के आई (I) को भी शामिल किया है। वर्ष 2026-27 के लिए प्रदेश का यह बजट ज्ञानी के मार्गदर्शी सिद्धान्त पर तैयार किया गया है। जिसमें गरीब कल्याण, युवा शक्ति के कौशल विकास एवं रोज़गारोन्मुखी प्रशिक्षण, अन्नदाता की आय में वृद्धि, नारी सशक्तिकरण, आधारभूत सुविधाओं का विकास एवं प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करने का संकल्प है। वर्ष 2026-27 के 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपए के बजट में विकास के लिए पर्याप्त धन राशि रखी गई है, यह विकास और जनकल्याण के संकल्प की पूर्ति का परिचायक है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह बजट 'समृद्ध मध्यप्रदेश, सम्पन्न मध्यप्रदेश, सुखद मध्यप्रदेश, सांस्कृतिक मध्यप्रदेश' के सपने को साकार करने वाला है। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी प्रदेश की जनता पर किसी नए कर बोझ नहीं डाला गया है। सुशासन और सुप्रबंधन के लिए निरंतर

युवा कल्याण के लिए बजट में विशेष प्रावधान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रत्येक जनकल्याणकारी योजना के लिए पर्याप्त धनराशि दी जा रही है। मध्यप्रदेश देश के सबसे युवा तीन प्रदेशों में से एक है। युवा कल्याण के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रदेश में सांदीपनि विद्यालय, पीएम श्री महाविद्यालय, चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है।

नवाचार और विकास के सभी पैमानों को पूरा करता यह बजट अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विधानसभा में वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत होने के बाद यह विचार व्यक्त किए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार ने रोलिंग बजट को अपनाते हुए वार्षिक बजट को दीर्घकालिक दृष्टि से जोड़ा गया है। रोलिंग बजट प्रस्तुत करने वाला संभवतः मध्यप्रदेश, देश का पहला राज्य है। इस बजट से अगले तीन वर्ष के विकास का खाका खीचा जाएगा और यह बजट विकास के लिए सतत् रूप से पर्याप्त धन राशि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। यह बजट अमृतकाल 2047 के लिए विकास का पैमाना सिद्ध होगा। वर्ष 2026-27 में राज्य का सकल घरेलु उत्पाद 18 लाख 48 हजार 274 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो वर्ष 2025-26 के अनुमान में 10.69 प्रतिशत अधिक है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में वर्ष 2024-25 की तुलना में वर्ष 2025-26 में 9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वर्ष 2026-27 में पूंजीगत परिव्यय राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 4.80 प्रतिशत अनुमानित है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता वृद्धि के लिए 28 हजार 158 करोड़ रूपए, आदान व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 64 हजार 995 करोड़ रूपए, उपज का बेहतर मूल्य दिलाने के लिए 8 हजार 91 करोड़ रूपए, सुरक्षा चक्र के लिए 13 हजार 769 करोड़ रूपए सहित कृषि कल्याण के लिए कुल 1 लाख 15 हजार 13 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है।

शहरों में अधोसंरचना विकास के लिए 'द्वारका योजना'

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ महापर्व से संबंधित 13 हजार 851 करोड़ के कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिसके अंतर्गत वर्ष 2026-27 के लिए 3 हजार 60 करोड़ रूपये का प्रावधान है। शहरों में अधोसंरचना विकास के लिए 'द्वारका योजना' में आगामी तीन वर्षों में 5 हजार करोड़ रूपये का निवेश संभावित है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि पर मालिकाना अधिकार की योजना है, जिसमें मुद्रांक एवं पंजीयन का समस्त शुल्क राज्य शासन वहन करेगा। यह देश में अपने तरह का पहला नवाचार है। इसके लिए 3 हजार 800 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

बच्चों को बेहतर पोषण के लिए यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना में 700 करोड़ रूपए का प्रावधान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बच्चों को बेहतर पोषण मिले, इसके लिए यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के लिए 700 करोड़ रूपये का प्रावधान है। इस योजनातंर्गत आगामी पांच वर्षों में 6 हजार 600 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए 23 हजार 883 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। किसी भी लाड़ली बहना को उसके अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा और सरकार निर्धारित समय-सीमा में लाड़ली बहनाओं को दी जाने वाली राशि का लक्ष्य प्राप्त करेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एण्ड आजीविका मिशन (ग्रामीण) के लिए 10 हजार 428 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

प्रदेश के इतिहास में पहली बार अधोसंरचना विकास के लिए एक लाख करोड़ रूपए से अधिक का प्रावधान

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार अधोसंरचना विकास में बजट अनुमान 2026-27 का पूंजीगत परिव्यय रुपये 1 लाख करोड़ रूपये से अधिक है। राज्य सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के समुचित प्रावधान किए हैं। प्रदेश के गठन के बाद पहली बार इतनी बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारा फोकस सर्वस्पर्शी, समावेशी विकास, सुशासन, पर्यावरण, पर्यटन एवं सांस्कृतिक पुनर्उत्थान पर है। सभी क्षेत्रों में विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में समृद्ध मध्यप्रदेश की दिशा में ऐतिहासिक बजट : मंत्री विश्वास कैलाश सारंग

सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने बुधवार को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट 2026-27 को विकास, जनकल्याण और आर्थिक अनुशासन का संतुलित एवं दूरदर्शी दस्तावेज बताते हुए कहा कि यह बजट प्रदेश को विकसित भारत 2047 के संकल्प की दिशा में अग्रसर करने वाला है। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि डबल इंजन सरकार के माध्यम से विकास और कल्याण की गाड़ी तेज गति से आगे बढ़ेगी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में मध्यप्रदेश की सार्थक भूमिका सुनिश्चित होगी। श्री सारंग ने कहा कि वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत बजट मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार का तीसरा बजट है, जिसका कुल आकार 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रूपये है। यह प्रदेश का पहला रोलिंग बजट है और वर्ष 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए 3600 करोड़ रूपये का विशेष प्रावधान किया गया है। बिना कोई नया टैक्स लगाए विकास को गति देना सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी को दर्शाता है।

कौशल विकास एवं रोजगार पर केंद्रित बजट युवाओं के भविष्य को देगा नई दिशा : मंत्री श्री टेटवाल

कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम टेटवाल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करने वाला और रोजगार सृजन को गति देने वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि GYANII आधारित बजट संरचना में युवा शक्ति को केंद्र में रखकर

कौशल उन्नयन, अप्रेंटिसशिप और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नेतृत्व में बजट आत्मनिर्भर, कुशल और सशक्त युवा शक्ति के माध्यम से समृद्ध मध्यप्रदेश के निर्माण को नई गति देगा। राज्यमंत्री श्री टेटवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए 750 करोड़ रूपये पोलीटेक्निक संस्थाओं के लिए 295 करोड़ रु., स्वशासी तकनीकी संस्थाओं को सहायता के लिए 250 करोड़ रु. और ए.डी.वी. परियोजना (कौशल विकास) के लिए 110 करोड़ रूपये का प्रावधान युवाओं की तकनीकी क्षमता को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना और सी. एम. युवा शक्ति योजना के लिए 100-100 करोड़ रूपये तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए 95 करोड़ रूपये प्रावधान उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इंजीनियरिंग महाविद्यालयों और शिक्षा प्रोत्साहन योजनाओं के लिए 70-70 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प पर आधारित प्रदेश के समग्र विकास का बजट : खाद्य मंत्री श्री राजपूत

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मार्गदर्शन में उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत बजट का मुख्य फोकस प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के संकल्प गरीब कल्याण, युवा शक्ति, अन्नदाता, नारी शक्ति, इन्फ्रास्ट्रक्चर, इन्डस्ट्री का सर्वांगीण विकास है। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविन्द सिंह राजपूत ने कहा है कि बुधवार को प्रस्तुत यह बजट सामाजिक सुरक्षा, कृषि सुदृढ़ीकरण, औद्योगिक निवेश और अधोसंरचना विकास के संतुलित संयोजन के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देने

की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मंत्री श्री राजपूत ने कहा है कि बजट में सभी वर्गों के कल्याण के लिए समुचित प्रावधान किये गए हैं। विशेष रूप से खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के लिए गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 531 करोड़ अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। इससे विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आयेगी। 'रोलिंग बजट' जैसी नवाचार पहल से वित्तीय योजना अधिक पारदर्शी और परिणामोन्मुखी बनेगी।

जनता के लिए निराशाजनक बजट : भाकपा

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने विधान सभा में 18 फरवरी को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा प्रस्तुत मध्य प्रदेश सरकार के बजट को गरीबी,महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त जनता के लिए निराशाजनक निरूपित किया है।भाकपा ने बजट के प्रस्तावों में जनहित से जुड़ी भाकपा की मांगों की उपेक्षा करने पर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की कड़ी भर्त्सना की है।

भाकपा मध्य प्रदेश के राज्य सचिव कॉमरेड शैलेन्द्र शैली ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के बजट में गरीबी ,महंगाई और बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई प्रभावकारी प्रस्ताव नहीं है। पेट्रोलियम पदार्थों पर मध्य प्रदेश सरकार ने अपना भारी टैक्स कम नहीं किया।भाजपा द्वारा चुनावों के लिए किए गए वादे भी पूरे नहीं किए गए।मध्य प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी में सरकारी नौकरी बंद है ।

बजट 2026-27 'समृद्ध मध्यप्रदेश 2047' के लक्ष्य की प्राप्ति में सशक्त कदम : राज्यमंत्री श्री पटेल

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को दूरदर्शी, समावेशी और जनकल्याणकारी बजट बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के सशक्तिकरण के साथ औद्योगिकीकरण और अधोसंरचना विकास को गति देने वाला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सशक्त, नेतृत्व में यह बजट 'समृद्ध मध्यप्रदेश @2047' के लक्ष्य की प्राप्ति में यह सशक्त कदम है। उन्होंने सर्वस्पर्शी भविष्योन्मुख बजट के लिए उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा का आभार व्यक्त किया है।राज्यमंत्री श्री पटेल ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2026-27 के लिए 23,747 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण, सुपरस्पेशियलिटी सेवाओं के विस्तार, आधुनिक उपकरणों की उपलब्धता और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवश्यक प्रावधान किए गए है। राज्यमंत्री श्री पटेल ने विश्वास व्यक्त किया कि यह बजट प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त कर वर्ष-2047 तक मध्यप्रदेश को विकसित राज्य बनाने में सहायक होगा।

भारत के प्रशिक्षित दंत चिकित्सक दंत चिकित्सा क्षेत्र में वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार : उप मुख्यमंत्री शुक्ल

इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल डेंटिस्ट्री 2026 का किया शुभारंभ

भोपाल (नप्र)। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि दंत चिकित्सा स्वास्थ्य व्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है। अच्छा मौखिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत के प्रशिक्षित दंत चिकित्सक दंत चिकित्सा क्षेत्र में वैश्विक अवसरों का लाभ उठाने के लिए तैयार हैं। उप मुख्यमंत्री शुक्ल एलएन मेडिकल कॉलेज भोपाल में 'इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्लोबल डेंटिस्ट्री-2026' के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे ने की। उन्होंने कहा कि यह पहल 'ब्रेन ड्रेन' नहीं बल्कि 'ग्लोबल गेन' का उदाहरण है। सही मार्गदर्शन, पारदर्शी प्रक्रिया और नैतिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भारतीय डेंटिस्ट वैश्विक मंच पर अपनी पहचान स्थापित कर सकते हैं तथा देश की प्रतिष्ठा को सशक्त बना सकते हैं।

सम्मेलन में पहली बार भारत में यूके डेंटल भर्ती एवं प्लेसमेंट पर संरचित मंच प्रस्तुत किया गया। ओआरई, एलडीसी, एमएफडीएस परीक्षाओं, जनरल डेंटल काउंसिल (जीडीसी) रजिस्ट्रेशन, वीज़ा/स्पॉन्सरशिप प्रक्रिया, यूके क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स, रोगी सुरक्षा और प्रोफेशनल एथिक्स पर विस्तृत जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को गलत सूचना और फर्जी एजेंसियों से बचने के लिए पारदर्शी प्रक्रिया समझाई गई। सम्मेलन में भारत एवं यूके की आय संभावनाओं की तुलनात्मक जानकारी भी प्रस्तुत की गई। यूके से आए विशेषज्ञों द्वारा वन-टू-वन मार्गदर्शन, पैनल डिस्कशन तथा दो दिवसीय सीपीडी एवं पर्सनलाइज्ड क्लिनिक का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में डेंटल सर्जन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. चंद्रेश शुक्ला, डॉ. अनुपम चौकसे, श्री धर्मेन्द्र गुप्ता, सहित दंत चिकित्सा विशेषज्ञ एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। लंदन से आए विशेषज्ञ डॉ. रूथ चेसमोर-होस्कर, डॉ. गौरी प्रधान, डॉ. शिवानी भंडारी, डॉ. दलिप कुमार, श्री विलियम नील कार्माइकल एवं डॉ. टिमोथी ओ'ब्रायन ने प्रतिभागियों को प्रत्यक्ष मार्गदर्शन प्रदान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दंत छात्र-छात्राओं, इंटर्न्स, प्रैक्टिसिंग दंत चिकित्सकों एवं फैकल्टी सदस्यों ने सहभागिता की और विशेषज्ञों से सीधे संवाद कर अपने कैरियर संबंधी प्रश्नों के समाधान प्राप्त किए।

सभी विधानसभा क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर स्थानीय परम्परागत उद्यमों को बढ़ावा दिया जाएगा : मंत्री श्री काश्यप

भोपाल (नप्र)। एमएसएमई मंत्री श्री चैतन्य कुमार काश्यप ने कहा है कि विभाग का प्रयास है कि जल्दी ही प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर स्थानीय परम्परागत उद्यमों को बढ़ावा दिया जाएगा। मंत्री श्री काश्यप विधानसभा स्थित समिति कक्ष में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की परामर्शदात्री समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे।बैठक में विधायक श्री ओमप्रकाश सखलेचा,श्री राजेश शुक्ला और श्री सतीश मालवीय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

मंत्री श्री काश्यप ने बैठक को सार्थक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में निवेश और उद्योगों के लिए सकारात्मक वातावरण बना है और देश विदेश के निवेशक मध्यप्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने सदस्यों को आश्वस्त किया कि विभाग बायोटेक्नोलॉजी पार्क के निर्माण के परीक्षण के साथ ही रैंप योजना के तहत उद्यमियों का एक्सपोजर विजिट करवाकर उनकी कार्यकुशलता बढ़ाने का काम करेगी।उन्होंने विभाग का बजट में लगातार वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री डॉ यादव का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह वर्ष किसान वर्ष है और विभाग खाद्य प्रसंस्करण आदि उद्योगों की स्थापना में समन्वय करेगा। मंत्री श्री काश्यप कि प्रदेश के शेष 79 विधानसभा क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने का कार्य जारी है और इसके पूरा होते ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में औद्योगिक क्षेत्र हो जाएंगे।

इतिहासकार शंभुदयाल गुरु को भावभीनी श्रद्धांजलि

भोपाल। इतिहासकार कीर्तिशेष शंभुदयाल गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय सभागार में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।

मध्य प्रदेश गठन के साथ प्रदेश के इतिहास को संजोने और उसे व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में शंभु दयाल गुरु ने प्रमुख भूमिका का निर्वहन किया था। इस दृष्टि से देखा जाए तो वह केवल एक इतिहासकार ही नहीं,बल्कि प्रदेश के अनेक लोगों को इतिहास बोध की समझ देने वाले मार्गदर्शक भी रहे।

स्वर्गीय शंभुदयाल गुरु की स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए उक्त उद्गार डॉ.सुशील त्रिवेदी ने व्यक्त किए। इतिहास परिषद की स्थापना में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण किया था।

सप्रे संग्रहालय के संस्थापक विजयदत्त श्रीधर ने कहा कि संग्रहालय की स्थापना में जिन लोगों का संबल रहा है,उनमें शंभु दयाल गुरुजी अग्रगण्य थे। पलाश सुरजन ने कहा कि गुरु जी ज्ञान का भंडार थे। समाचार पत्र में छप रही सामग्री पर उनका मार्गदर्शन तो मिलता ही था, गलतियों पर डांट भी मिलती थी।

रामप्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि मैंने भोपाल को गुरु जी के मार्फत समझा। वह छोटी-छोटी जिज्ञासाओं का समाधान भी पूरी प्रामाणिकता के साथ करते थे। ध्रुव शुक्ल ने कहा कि गुरु जी प्रवीणता, प्रामाणिकता और पारिदर्शिता के जीवंत उदाहरण थे। प्रभु दयाल मिश्र ने गुरुजी के व्यक्तित्व और कृतित्व को अनुकरणीय बताया रघुराज सिंह ने कहा कि गुरुजी जीवंत इतिहास थे। श्रद्धांजलि सभा को ए के विजयवर्गीय, डॉ. हंसा व्यास ने भी संबोधित किया। श्रद्धांजलि सभा का संचालन सप्रे संग्रह के निदेशक अरविन्द श्रीधर ने किया।

संपादकीय

मप्र: अंतहीन कर्ज

मप्र की मोहन यादव सरकार का कर्ज पर कर्ज लेने का सिलसिला थमता नजर नहीं आ रहा है। वर्ष 2025-26 के तीसरे अनुपूरक बजट के साथ ही सरकार अब बाजार से 5600 करोड़ रुपए के चार नए कर्ज लेने जा रही है। यह राशि नए वर्ष के बजट के साथ मिलेगी। कर्ज की इस नई किश्त के साथ ही मप्र सरकार पर चालू साल में कुल कर्ज का आंकड़ा 72900 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा जो अब तक के इतिहास में सर्वाधिक है। इन चार कर्जों के साथ साढ़े दस माह में लिए गए कर्ज की कुल संख्या भी 40 हो जाएगी। मंगलवार को राज्य सरकार जो चार नए कर्ज ले रही है उसमें से पहला कर्ज 1200 करोड़ रुपए का है, जो 8 साल के लिए होगा। दूसरा कर्ज 1400 करोड़ रुपए का 13 साल की अवधि के लिए लिया जा रहा है जबकि तीसरा कर्ज 1600 करोड़ रुपए का होगा और सरकार ब्याज के साथ इस राशि का भुगतान 19 साल में करेगी। चौथा कर्ज 1400 करोड़ रुपए का 23 साल की अवधि के लिए लिया जा रहा है। इन सभी कर्जों की अदायगी हर छह माह में की जाएगी। वित्त विभाग ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। फरवरी में लगातार तीसरे हफ्ते लिए जा रहे कर्ज के बाद अकेले इस माह में दस कर्ज हो जाएंगे। 10 फरवरी तक सरकार ने दस दिन के अंतराल से छह कर्ज लिए थे। वहीं चालू वित्त वर्ष में लिए जा रहे कुल कर्ज की संख्या 40 पहुंच जाएगी। इसके पहले 10 फरवरी को सरकार ने 5 हजार करोड़ और तीन फरवरी को 5200 करोड़ का कर्ज लिया था। लगातार मप्र सरकार की कमजोर वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। सरकार खर्च पर खर्च करती जा रही है, लेकिन पैसे जुटाने का कोई ठोस उपाय या मंशा उसके पास नहीं है। ऐसी कोई कोशिश होते भी नहीं दिखाई दे रही है। बहरहाल सरकार नीलामी के जरिए सिक्योरिटीज को बेचकर पैसे जुटाएगी। सिक्योरिटीज (प्रतिभूतियों) की यह नीलामी भारतीय रिजर्व बैंक कर रही है। आरबीआई के अनुसार, सिक्योरिटीज न्यूनतम रू. 10 हजार के नाममात्र मूल्य पर होगी। उधर सरकार का दावा है कि उसकी सम्पत्तियों में बढ़ोतरी हुई है। मप्र सरकार के मुताबिक भारत सरकार से समय-समय पर लिए गए ऋण मुख्य रूप से राज्य में उत्पादक योजनाओं और स्थायी संपत्तियों के निर्माण में उपयोग किए गए हैं। सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्र सरकार से स्वीकृत ऋण का उपयोग कृषि योजनाएं,सिंचाई एवं बिजली परियोजनाएं, समुदाय विकास परियोजनाएं, अन्य स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, भविष्य निधि और ब्याज वाले जमा में किया जाता है। ऋण राशि से प्रदेश में कई राजस्व देने वाली संपत्तियां बनाई गईं, जिनमें सिंचाई परियोजनाएं (बांध, नहर, टैंक, कुएं आदि), संचार और परिवहन सेवाओं में, सुधार, सहकारी बैंकों व सहकारी समितियों की शेयर पूंजी में निवेश, किसानों-स्थानीय निकायों को ऋण देने की व्यवस्था, ऊर्जा विभाग की कंपनियों को बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और वितरण में किया जाता है। सरकार जो भी दावे करे, लेकिन जो हालात सामने दिख रहे हैं, वो इसी बात का संकेत है कि राज्य का वित्तीय प्रबंधन ठीक नहीं है। एक समय था जब राज्य की भाजपा सरकार इस बात को गर्व के साथ कहती थी कि हम पर कोई ओवरड्राफ्ट नहीं है। लेकिन अब आए दिन कर्ज लेना पड़ रहा है। इस बीच गरीबी में आटा गीला की तर्ज पर यह खबर आई कि केन्द्रीय वित्त आयोग ने नए मानकों के हिसाब से मप्र की राशि 50 हजार करोड़ रू. कम कर दी है। यह राशि पांच वर्षों में घटेगी, लेकिन मप्र जैसे राज्य के लिए यह तगड़ा झटका है। ऐसा हुआ तो इस रकम की प्रतिपूर्ति भी कैसे होगी?

नेपाल में राजनीति की निर्णायक परीक्षा

हिंसा और प्रदर्शन के बाद नये सिरे से खड़े होने को तैयार नेपाल में चुनाव की तैयारी के दौरान सरकार ने नए मतदाताओं के पंजीकरण को आसान बनाया, युवाओं को नाम दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया और चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश की। एक प्रगतिशील कदम उठाते हुए विदेश में रहने वाले नेपाली नागरिकों को मतदान की सुविधा देने का विचार भी सामने आया, हालांकि तकनीकी और कानूनी कारणों से यह इस बार संभव नहीं हो सका। दिसंबर में अंतरिम सरकार ने आंदोलन से जुड़े कई नेताओं के साथ समझौता किया। इसमें संविधान में सुधार, चुनाव प्रणाली में बदलाव, न्यायपालिका और प्रशासन में पारदर्शिता, तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम जैसे मुद्दे शामिल थे। इन प्रदर्शनों को औपचारिक रूप से जन आंदोलन का दर्जा दिया गया, जिससे उन्हें नेपाल के ऐतिहासिक जनआंदोलनों की कड़ी में जोड़ा गया।

नजरिया

अंशुमान

लेखक संसद टीवी से सम्बद्ध पत्रकार हैं।

नेपाल एक बार फिर जनरेशन ज़ेड यानी युवाओं के नेतृत्व में हुए व्यापक प्रदर्शनों के पाँच महीने बाद निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे इन प्रदर्शनों ने देश की राजनीति की जड़ें हिला दी थीं और तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पद छोड़ना पड़ा। उसके बाद से देश में अंतरिम सरकार काम कर रही है, जिसकी कमान पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के हाथों में है। अब 5 मार्च को होने वाला चुनाव केवल नई सरकार चुनने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह नेपाल की लोकतांत्रिक दिशा, राजनीतिक संस्कृति और भविष्य की स्थिरता की भी परीक्षा है।

सितंबर में हुए प्रदर्शनों ने पूरे देश को झकझोर दिया था। कई जगह हिंसा, आगजनी और टकराव की घटनाएँ सामने आयीं। हालात बिगड़ने पर राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने सेना और आंदोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे समूहों से बातचीत के बाद अंतरिम व्यवस्था लागू की। प्रतिनिधि सभा को भंग कर नए चुनाव का रास्ता साफ किया गया। कार्की के नेतृत्व वाली इस गैर-राजनीतिक अंतरिम सरकार का मुख्य काम था–देश में शांति बहाल करना, निष्पक्ष चुनाव कराना और युवाओं की उन मांगों पर विचार करना जो लंबे समय से अनसुनी की जा रही थीं।

हिंसा और प्रदर्शन के बाद नये सिरे से खड़े होने को तैयार नेपाल में चुनाव की तैयारी के दौरान सरकार ने नए मतदाताओं के पंजीकरण को आसान बनाया, युवाओं को नाम दर्ज कराने के लिए अतिरिक्त समय दिया और चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की कोशिश की। एक प्रगतिशील कदम उठाते हुए विदेश में रहने वाले नेपाली नागरिकों को मतदान की सुविधा देने का विचार भी सामने आया, हालांकि तकनीकी और कानूनी कारणों से यह इस बार संभव नहीं हो सका। दिसंबर में अंतरिम सरकार ने आंदोलन से जुड़े कई नेताओं के साथ समझौता किया। इसमें संविधान में सुधार, चुनाव प्रणाली में बदलाव, न्यायपालिका और प्रशासन में पारदर्शिता, तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम जैसे मुद्दे शामिल थे। इन प्रदर्शनों को औपचारिक रूप से जन आंदोलन का दर्जा दिया गया, जिससे उन्हें नेपाल के ऐतिहासिक जनआंदोलनों की कड़ी में जोड़ा गया।

अगर गहराई से आकलन करे तो नेपाल में आंदोलन पूरी तरह एकजुट नहीं रहा। कुछ समूहों के बीच विचारों में मतभेद सामने आए। राजशाही समर्थक संगठनों ने अंतरिम सरकार की वैधता पर सवाल उठाए और राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर कार्की के इस्तीफे की मांग की। इससे यह स्पष्ट हुआ कि नेपाल की राजनीति अभी भी कई धाराओं में बंटी हुई है।

लोकतांत्रिक गणराज्य, संवैधानिक सुधार, और कुछ वर्गों में राजशाही की वापसी की चाह जैसी अलग-अलग सोच साथ-साथ मौजूद हैं।

नेपाल आज जिस ऐतिहासिक दौर से गुजर रहा है, वह केवल चुनावी राजनीति का प्रश्न नहीं बल्कि लोकतांत्रिक परिपक्वता की परीक्षा भी है। 2008 में नेपाल ने खुद को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया था। लेकिन तब से अब तक चौदह प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। सरकारें

अक्सर गठबंधन पर टिकी रहीं और थोड़े समय में गिरती-बनती रहीं, और इसी अस्थिरता ने युवाओं के असंतोष को आक्रोश में बदल दिया और फिर जो हुआ उसे पूरे विश्व ने देखा। उन्हें लगा कि राजनीतिक दल आपसी खींचतान और सत्ता संतुलन में उलझे हैं, जबकि आम जनता के मुद्दे जैसे रोजगार की कमी, महंगाई, शिक्षा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सेवाएँ, और विदेश पलायन जैसे के तैसे हैं।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) के नेता केपी शर्मा ओली ने इन प्रदर्शनों को अपनी राष्ट्रवादी नीतियों के खिलाफ साजिश बताया। उन्होंने संसद भंग करने के फैसले को सही ठहराया और अदालत में चुनौती भी दी। हालांकि इसमें भी उनकी खुद की पार्टी में मतभेद सामने आये और कुछ नेताओं ने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव की तैयारी भी कर रही है, जबकि दूसरी ओर अंतरिम सरकार को असंवैधानिक भी बता रही है। और कुछ नेताओं ने यह भी माना कि युवाओं की मांगों में दम है और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

दूसरी तरफ नेपाली कांग्रेस में भी बदलाव की लहर चली। वरिष्ठ नेता शेर बहादुर देउबा पर जनता का दबाव बढ़ा। पार्टी के युवा चेहरे गगन थापा ने खुले तौर पर सुधार की बात की। पार्टी में आंतरिक चुनाव और नेतृत्व परिवर्तन को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद थापा के नेतृत्व में नया ढांचा बना। उन्होंने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में खुद को प्रस्तुत किया और कई सुधार प्रस्ताव रखे जैसे प्रधानमंत्री के लिए कार्यकाल सीमा, टिकट वितरण में पारदर्शिता, भाई-भतीजावाद पर रोक, और भ्रष्टाचार के मामलों की निष्पक्ष जांच।

इन्हीं सबके बीच में माओवादी धड़ा भी सक्रिय हुआ। पुष्प कमल दहल के नेतृत्व में छोटे वामपंथी दलों के साथ मिलकर नया गठबंधन बना। वहीं, नई राजनीति का दावा करने वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने खुद को पारंपरिक दलों के विकल्प के रूप में पेश किया और इसके प्रमुख रबी लामिचने ने अन्य नए चेहरों के साथ मिलकर व्यापक मोर्चा बनाने की कोशिश की। काठमांडू के मेयर बालेन शाह और पूर्व ऊर्जा प्रमुख कुलमन घीसिंग के साथ भी एक राजनीतिक प्रयास हुआ, लेकिन वह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। इन सबके बीच नेपाल की राजनीति को करीब से देखने वाले मानते हैं कि नेपाल की वैकल्पिक राजनीति भी अपने भीतर चुनौतियों से घिरी है।

हमें एक बात समझने की जरुरत है कि प्रदर्शनों के बाद हो रहे इन चुनावों का महत्व केवल सत्ता परिवर्तन तक सीमित नहीं है बल्कि यह युवाओं के विश्वास की परीक्षा है। लगभग आधे से अधिक मतदाता 18 से 40 वर्ष की आयु के हैं, लेकिन प्रमुख दलों में युवाओं की भागीदारी अभी भी सीमित है। राजनीतिक नेतृत्व नई पीढ़ी को आगे आने का पूरा अवसर देने में झिझकता दिखाई देता है। यही कारण है कि बदलाव की प्रक्रिया धीमी और कठिन लगती है।

नेपाल के सामने कई बड़े मुद्दे और चुनौतियां हैं जैसे आर्थिक सुधार, रोजगार सृजन, पर्यटन और जल विद्युत क्षेत्र का विकास, विदेश में काम करने गए नेपाली युवाओं की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार, तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण बड़े मुद्दे हैं। साथ ही कूटनीतिक नजरिये से हम देखें तो नेपाल की भारत और चीन जैसे बड़े पड़ोसी देशों के बीच संतुलन बनाए रखना भी एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक चुनौती है। एक बात तो तय है कि आने वाली सरकार चाहे किसी भी दल की हो, उससे जनता की अपेक्षाएँ बहुत अधिक हैं। अगर वह युवाओं की आवाज को अनसुना करती है, तो असंतोष फिर उभरने की आशंका को हम नकार नहीं सकते हैं। फिर भी उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। युवाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी, नागरिक समाज की सक्रियता और पारदर्शिता की मांग यह संकेत देती है कि समाज बदलाव के लिए तैयार है। सवाल केवल नेतृत्व का नहीं, बल्कि राजनीतिक संस्कृति का है, क्या दल अल्पकालिक सत्ता समीकरणों से ऊपर उठकर दीर्घकालिक नीतिगत स्थिरता पर ध्यान देंगे? लेकिन अगर राजनीतिक दल ईमानदारी से सुधार की दिशा में कदम उठाते हैं, तो यह चुनाव नेपाल की लोकतांत्रिक यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत बन सकता है।

राजनीतिक इच्छाशक्ति यहाँ निर्णायक कारक बनेगी। सुधारों चाहे वे सुशासन, भ्रष्टाचार नियंत्रण, आर्थिक पुनरुत्थान या संघीय ढांचे के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़े हों के लिए निरंतरता और धैर्य दोनों आवश्यक हैं। जनता की अपेक्षाएँ अब केवल वादों तक सीमित नहीं हैं वे परिणाम देखना चाहती है। अंततः यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का माध्यम बनेगा या एक नई राजनीतिक संस्कृति की शुरुआत करेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि नेतृत्व कितनी ईमानदारी से जवाबदेही स्वीकार करता है और क्या वह दीर्घकालिक राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देता है। यही मोड़ तय करेगा कि निराशा भारी पड़ेगी या उम्मीद एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी।

हरित भविष्य: किसकी चलेगी दुनिया में?

मोहन सरकार उपलब्धि

कुमार सिद्धार्थ

लेखक स्तंभकार हैं।

आज की दुनिया ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जहाँ जलवायु संकट मानव सभ्यता के भविष्य को तय करने वाला बड़ा प्रश्न बन चुका है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि कोयला, तेल और गैस पर हमारी निर्भरता जल्द कम नहीं हुई तो धरती का तापमान ऐसे स्तर तक पहुँच जाएगा, जहाँ जीवन की वर्तमान संरचनाएँ टिक नहीं पाएँगी। इसके बावजूद वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा आज भी जीवाश्म ईंधनों के इर्द-गिर्द घूम रहा है। इस पूरी व्यवस्था की भयावह बात यह है कि जब कोई सरकार पर्यावरण और जनता के हित में कदम उठाने की कोशिश करती है, तो उसे 'न्याय' के नाम पर दंडित किया जाता है।

पिछले कुछ दशकों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश समझौतों के ज़रिये एक ऐसा कानूनी ढांचा खड़ा किया गया है, जिसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ सरकारों पर मुकदमा कर सकती हैं। इसे 'निवेशक-राज्य विवाद निपटान प्रणाली' (आईएसडीएस) कहा जाता है। इसके तहत यदि कोई सरकार पर्यावरण, स्वास्थ्य या सामाजिक हित में ऐसा निर्णय लेती है, जिससे किसी कंपनी के मुनाफे पर असर पड़ता है, तो वह कंपनी सरकार से न केवल अपने निवेश की भरपाई, बल्कि 'संभावित भविष्य के मुनाफे' का भी दावा कर सकती है। ये मुकदमे सामान्य अदालतों में नहीं, बल्कि गुप्त ट्रिब्यूनलों में चलते हैं, जहाँ न पारदर्शिता होती है, न जनता की भागीदारी और न ही लोकतांत्रिक जवाबदेही।

यह व्यवस्था अपने आप में लोकतंत्र के लिए एक गहरा खतरा है। सरकारें जनता द्वारा चुनी जाती हैं, ताकि वे जनता और पर्यावरण के हित में फैसले लें। लेकिन आईएसडीएस जैसे प्रावधानों के कारण वही सरकारें कंपनियों के डर से पीछे हटने लगती हैं। आईएसडीएस की मार सबसे पहले उन देशों पर पड़ी है, जिन्होंने पर्यावरण और जनता के हित में साहसिक फैसले लिए। जर्मनी ने जब परमाणु ऊर्जा से बाहर निकलने का निर्णय किया तो ऊर्जा कंपनी वाटनफॉल ने उस पर अरबों यूरो का दावा ठोक दिया। पाकिस्तान ने एक खनन परियोजना को पर्यावरणीय कारणों से रोका तो उस पर छह अरब डॉलर से अधिक का जुर्माना लगाया गया, जो उसके पूरे शिक्षा और स्वास्थ्य बजट से भी ज़्यादा था। स्लोवेनिया में एक ब्रिटिश कंपनी को केवल यह कहने पर कि फ्रैकिंग से पहले पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन ज़रूरी है, सरकार पर 120 मिलियन यूरो का मुकदमा कर दिया गया और अंततः सरकार को झुकना पड़ा। कोलंबिया में आदिवासी समुदायों के संघर्ष से एक कोयला खदान परियोजना रुकी, लेकिन कंपनियों ने ब्रिटेन-कोलंबिया संधि के तहत सरकार से मुआवज़ा वसूल लिया।

इन उदाहरणों का खतरनाक असर यह है कि सरकारें पर्यावरण बचाने से पहले अब यह सोचने लगती हैं कि कहीं उन्हें अंतरराष्ट्रीय अदालतों में अरबों डॉलर का हर्जाना न भरना पड़ जाए। इसे 'रेगुलेटरी चिल' कहा जाता है, यानी कानून बनाने की हिम्मत तो रहती है, मगर उन्हें लागू करने का साहस नहीं बचता। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ ने इस व्यवस्था को 'कानूनी आतंकवाद' निरूपित किया है, क्योंकि यह सरकारों को डराकर लोकतांत्रिक फैसलों को पलटने का हथियार बन चुकी है।

लेकिन यह प्रक्रिया केवल कानूनी तंत्र तक सीमित नहीं है। इसका एक और, उससे भी अधिक क्रूर रूप वेनेजुएला में देखने को मिलता है। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। लंबे समय से यह देश अमेरिकी साम्राज्यवाद और वैश्विक तेल कंपनियों की नज़र में खटकता रहा है, क्योंकि उसने अपने तेल संसाधनों पर राष्ट्रीय नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। अमेरिका ने वहाँ की निर्वाचित सरकार को अस्थिर करने के लिए आर्थिक प्रतिबंध लगाए, उसकी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने की कोशिश की और खुले तौर पर सत्ता परिवर्तन की राजनीति चलाई। तेल के लिए एक संप्रभु देश के लोकतंत्र को कुचल देना और अंतरराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियाँ उड़ाना यह दिखाता है कि जब संसाधनों का सवाल आता है, तो लोकतंत्र और मानवाधिकार कितने बौने साबित हो जाते हैं।

अब सवाल यह है कि भारत इस पूरी तस्वीर में कहाँ खड़ा है? क्या हम खुद को इस खतरे से सुरक्षित मान सकते हैं? शायद नहीं। भारत आज तेज़ी से वैश्विक पूंजी और निवेश के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। कोयला खनन, तटीय औद्योगिक परियोजनाएँ, परमाणु संयंत्र, बड़े बाँध, तेल और गैस की खोज ये सभी क्षेत्र पहले से ही पर्यावरण और स्थानीय समुदायों के अधिकारों को लेकर विवादों में घिरे हुए हैं। यदि भविष्य में भारत ऐसे निवेश समझौतों का हिस्सा बनता है, जिनमें आईएसडीएस जैसे प्रावधान होंगे, तो हमारी सरकारों पर भी वही दबाव आएगा, जो आज कई अन्य देशों पर है।

भारत में पर्यावरणीय मंज़ूरी की प्रक्रियाओं को 'विकास में बाधा' बताकर कमजोर किया जा रहा है। कई बार परियोजनाओं को तेजी से मंज़ूरी देने के लिए नियमों में ढील दी जाती है, जनसुनवाई को औपचारिकता बना दिया जाता है और स्थानीय लोगों की आपत्तियों को अनदेखा कर दिया जाता है। यदि इसके ऊपर अंतरराष्ट्रीय मुकदमों का डर भी जुड़ गया, तो पर्यावरण संरक्षण लगभग असंभव हो जाएगा। तब सरकारें जनता और प्रकृति के नहीं, बल्कि निवेशकों और कंपनियों के प्रति जवाबदेह होंगी।

भारत जैसे देश के लिए यह विशेष रूप से खतरनाक है, क्योंकि यहाँ विकास की कीमत पहले गरीब, आदिवासी और हाशिए पर पड़े समुदाय चुकाते हैं। जंगलों से विस्थापन, खनन से प्रदूषण, नदियों के सूखने और ज़मीन के बंजर होने से उनकी आजीविका छिन जाती है। यदि सरकारें अंतरराष्ट्रीय दबाव में आकर पर्यावरणीय फैसलों से पीछे हटने लगेंगी, तो इन समुदायों के अधिकार पूरी तरह कुचल दिए जाएँगे।

वेनेजुएला का उदाहरण और आईएसडीएस जैसी कानूनी व्यवस्थाएँ मिलकर यह साफ कर देती हैं कि आज का वैश्विक तंत्र संसाधनों की रक्षा के नाम पर नहीं, बल्कि संसाधनों की लूट को वैध ठहराने के लिए खड़ा किया गया है। एक तरफ़ कहा जाता है कि दुनिया को जलवायु संकट से बचाना है, दूसरी तरफ़ उन कंपनियों को कानूनी और राजनीतिक संरक्षण दिया जाता है जिनका अस्तित्व ही इस संकट को गहराने पर टिका है।

भारत को इस पूरे परिदृश्य से गंभीर सबक लेना चाहिए। हमें ऐसे किसी भी अंतरराष्ट्रीय समझौते से सावधान रहना होगा जो हमारी लोकतांत्रिक संप्रभुता और पर्यावरण संरक्षण की क्षमता को कमजोर करता हो। संसद को यह अधिकार मिलना चाहिए कि वह व्यापार और निवेश समझौतों की पूरी तरह समीक्षा करे, उन पर बहस करे और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें अस्वीकार भी कर सके।

भारत को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यह संदेश देना चाहिए कि जलवायु कार्रवाई को 'निवेशकों के अधिकार' के नाम पर कुचला नहीं जा सकता। पर्यावरण रक्षा कोई आर्थिक बाधा नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व का प्रश्न है। यदि सरकारें डर और दबाव में आकर सही फैसले नहीं ले पाएँगी, तो लोकतंत्र केवल एक खोखला ढांचा बनकर रह जाएगा। भारत जैसे देशों के लिए यह समय चेतने का है। विकास का अर्थ केवल जीडीपी बढ़ाना नहीं, बल्कि जीवन, पर्यावरण और लोकतंत्र की रक्षा करना भी है।

पुलिस : चाल, चरित्र और चेहरा

दृष्टिकोण

विजय जोशी

लेखक भेल के पूर्व ग्रुप महाप्रबंधक हैं।

हाल ही में 'नेशनल क्राइम इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो' द्वारा भ्रष्टतम विभागों की सूची में रिश्वतखोरी, अवैध वसूली, फर्जी केस की पर्याय प्रथम स्थान प्राप्त हमारी पुलिस तथा विदेशों में सहर्ष सहज उपलब्ध ईमानदार, मददगार पुलिस व्यवस्था का विनम्र अवलोकनः

अमेरिकी पुलिस- यह घटना अमेरिका स्थित फ्लोरिडा नगर की है। छोटी बेटी और नातिन के साथ हम डिस्नी वर्ल्ड भ्रमण पर थे। बच्चे एक खास शो में रुचि रखते थे, सो उनका प्रवेश सुनिश्चित किया यथा समय लौटने का वचन देकर। यहां थी हर ओर गहमागहमी एवं भीड़। ठीक समय पर लौट भी आये पर इतने शो एक साथ छूट रहे थे कि हम परेशान होने लगे। इस परेशानी को पास ही खड़ा एक कॉप संभवतया देख रहा था। उसने हमारे पास आकर कहा यहां सब कुछ तय समय घड़ी के कांटो के साथ संपन्न होता है, सो परेशान न हों तथा हमें प्रतीक्षा का मश्विरा दिया। ठीक समय शो समाप्त हुआ। बच्चे बाहर आ गये। हमारी जान में जान आई। नज़र घुमाई तो देखा वही कॉप दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। दूर होने के बावजूद उसे हमारी चिंता थी। चलते समय उसने हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए हमारा अभिवादन भी किया।

न्यज़ीलैंड पुलिस- यह प्रसंग दुनिया के दक्षिण छोर पर स्थित देश का। अपार भूमि संपदा, जनसंख्या बहुत ही कम। मीलों तक न बसाहट और न ही मनुष्य मात्र के दर्शन। इसके बावजूद कानून व्यवस्था चाक चौबंद। पुलिस फोर्स बहुत कम, पर जो हैं वे बेहद सतर्क, जागरूकता और कर्तव्यनिष्ठ। यहां भारी वाहन चालक एक दिन में 8 घंटे से अधिक ड्राइव नहीं कर सकते और वह भी 4 घंटो के बाद ब्रेक के साथ। चालक के पास लॉग बुक और उसमें प्रविष्टि अनिवार्य। सो अधिकाधिक स्थल देखने के आदी टूरिस्टों के निशाने पर सदैव ड्राइवर, जो सारे दबाव सहर्ष झेलता है।

हमारी यात्रा के दौरान एक दिन सुनसान राजमार्ग पर एक कॉप अचानक प्रकट हुआ एवं गाड़ी रुकवा दी। सारे यात्री सहम गए। कॉप ने आश्वस्त किया कि यह रूटीन चेक मात्र है। ड्राइवर ने शांति के साथ सारे पेपर्स चेक करवा दिये और यात्रा निर्बाध जारी रही। कुरेदने पर बताया कि यहां हर चीज़ कैमरे की निगरानी में है। झूठी लॉग बुक

भरना संभव ही नहीं। गलती करके पकड़े जाने पर सजा भी अपराध के अनुरूप अनिवार्य।

ऐसे अनेकों प्रसंग याद हैं जिनसे वहां की कार्यप्रणाली को समझा जा सकता है। इनाम देने की कोशिश उनके आत्मसम्मान पर चोट। अपराध की दशा में बच पाने की कोई गुंजाइश नहीं। कानून सबके लिये समान, कोई भेदभाव नहीं। राजनैतिक दबाव या पैसे की कोशिश का एकमात्र स्थान जेल की कोठरी। वहां महात्मा गांधी के शब्दों में पाप से घृणा की जाती है पापी से नहीं।

निष्कर्ष : कुल मिलाकर यही फ़र्क है भ्रष्टाचारी, अनाचारी एवं सदाचारी व्यवस्था में। आशा करें किसी दिन हमारी संस्कृति और सभ्यता भी ढलेगी और हम अपनों के लिये भी कह सकेंगे -

कितने हसीन लोग हैं, जो मिल के एक बार
आंखों में जज़्ब हो गए, दिल में समा गए।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

मुएं, ये बेहाल करते हाल-चाल जानने वाले

व्यंग्य

डॉ. प्रेमचंद द्वितीय

लेखक व्यंग्यकार हैं।

गांव के फुंदीलाल मामा जी के हाथ पैर एकाएक सुन्न हो गए और वह पैरालिटिक अटैक के जद में आ गए तो उनके छोकरो ने समीप के महानगर में अच्छे इलाज की सुविधा होने के बावजूद अपने भांजे के छोटे से कस्बे में इलाज कराना सेवा-सुश्रुषा और आराम की दृष्टि से उचित समझा और भांजे के कस्बे में परिजनों के साथ पहुंच गए।

जब तंग मकान, दूध, सब्जी, शुद्ध पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जूझते हुए भांजे के मकान में जब लकवा ग्रस्त मामा जी ने डेरा जमाया तो पहले दिन तो भांजे ने खुले मन से मामा जी की सेवा और आवभगत की ।उनके कहने के मुताबिक कस्बे के कबाड़ी डॉक्टर को इलाज हेतु बतला दिया। तकिया ,पंखा ,नलकूप का पानी, गद्दा उस पर साफ चादर और बीवी बच्चों को मामा जी के हाथ पैर दबाने हेतु नियुक्त कर दिया। लेकिन अनायास दूसरे तीसरे दिन ही भांजे को इन सारी सुविधाओं को सरकारी सुविधा की तरह वापस लेना पड़ी, क्योंकि मामा जी का हाल-चाल जानने वाले गांव के लोगों की और रिश्तेदारों की आवाजाही से भांजा मामा जी की वजह से साक्षात नरक भुगतने को मजबूर हो गया

सुबह से देर रात मामा जी से राय मशविरा करने वाले और हाल-चाल जानने वालों के तांते ने उसे बेहाल कर दिया। उनके कुशल क्षेम पूछने वालों की चाय पानी करने में भांजे और भतीजे आजीज हो गए। तंग और संकरें मकान में मामाजी के हाल चाल जानने वाले मेहमानों की लाइन लगने लगी, उधर सफेद चादर पर बीड़ी के अद्दे और उसकी गंध से घर में धुंए से प्रदूषण होने लगा,ससुराल आए एकमात्र पंखे के लिए मामा, भांजे और रिश्तेदारों में उस पंखे के नीचे सोने की होड होने लगी। इन सारी सुविधाओं के बीच मामा जी का स्वास्थ्य सुधरने लगा उधर मामा जी के स्वास्थ्य सुधरने के स्थान पर भांजे की सेहत गिरने लगी,नौकर पैशा भांजे का बजट गड़बड़ा गया। महीने का बजट जो महीने के आखरी दिनों में गड़बड़ाता था वह 10 तारीख के आसपास हांफने लगा। हरी सब्जी खाने वाला भांजा और उसका परिवार आलू बैंगन तक के लिए मोहताज हो गया, मेहमान की भीड़ की वजह से उसकी रातें प्लेटफार्म पर रात गुजारने जैसी हो गई,किचन प्रेशर की वजह से रोमानी नजरों से रोज देखने और बात करने वाली भांजे की पत्नी की निगाह में भांजा और उसके मामा जी भी खटकने लगे।

इधर मामा जी की सेहत उनके समाचार लेने आने वाली महिलाओं द्वारा मांसल हाथों से लकवा ग्रस्त हाथ पैर दबाने से उनकी हालत लगातार सुधरती जा रही थी जो भी उनका समाचार लेने आते हैं,तरह तरह की राय और नुस्खे बताते, टीवी के परदे के बदलते सीन की तरह मामाजी घड़ियाली आंसू बहाते तो कभी सगाई सगपण और अन्य सामाजिक कार्यक्रम की बात करते, अनजान आदमी के सामने आंखों में आंसू लाकर ऐसा रोल निभाने की मामा जी कुछ ही दिनों के ही मेहमान है लेकिन उनके जाने के ठीक बाद अपने निकट सगे संबंधियों से रिश्ते मिलाने की चर्चा करने करते रहते हैं। भांजा तो उस दिन निढाल हो गया जब मामा जी ने गंगा दशमी के दिन अपनी बहन से पांच पचास आदमी का भोजन रखवा लिया और अपनी सेहत सुधार के लिए बहन की तरफ से इस आयोजन की गोटी फिट कर ली।

क्षेत्रीय दलों की तरह मामा जी के बढ़ते प्रभाव और उनके टिकने के अंदेशे से परेशान भांजे को एक युक्ति सूझी और मामा जी यहां से उनके घर चले जाए इसके लिए उन्होंने मंदिर जाकर भगवान से विनती की, विनती के दौरान उनके मन में आया कि उन्हें घर पहुंचा दे क्योंकि उनके अट्टहास और मक्कारी उसके ध्यान में आ गई , भांजे को सौम्य मामा जी में कंस की सूरत परिलक्षित होने लगी। भांजे को एक और युक्ति दिमाग में आई वह सीधा मामा जी का इलाज कर रहे डॉक्टर कबाड़ी के पास गए और उसने डॉक्टर कबाड़ी से जुगाड़ लगाते हुए बोला कि आपको जो भी फीस लगे,आप घर जाकर मामा जी को सलाह दे दे कि अब आपका स्वास्थ्य अच्छा हो गया है आप एक महीने की दवाई लेकर के गांव चले जाओ,कबाड़ी चिकित्सक को जुगाड़ की राशि मिलने पर वह मामा जी के पास पहुंचा और मामा जी से कहा कि आपको पंखे की हवा सूट नहीं होगी, यहां का मटमैला पानी और बीमार कर देगा,खुली हवा में सोने से आपका रोग जल्दी कटेगा। आपके हाल-चाल जानने वाले भी प्राकृतिक नुस्खों से आपके हाल और चाल दोनों में ही रवानी दे देंगे। मामाजी की रवानी और उनका रवाना होना भांजे को बेहाली से मुक्त करने का माध्यम बना। और भांजे ने भगवान से प्रार्थना की कि इन मुएं,हाल-चाल जानने वाले, राय चंदों की बेहाल करने प्रवृति से निजात दिलाना!

शिवाजी और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश

शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के दुर्गम और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शिवनेरी किला में हुआ था। इसलिए 19 फरवरी को उनकी जयंती बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। यह दिन केवल एक ऐतिहासिक स्मृति नहीं, बल्कि भारतीय समाज के लिए राष्ट्र गौरव, स्वाभिमान और सहिष्णुता के मूल्यों को पुन: स्मरण करने का अवसर भी है। उनकी माता जीजाबाई ने बचपन से ही उनमें धर्म, नीति, करुणा और न्याय के संस्कारों का रोपण किया, जबकि पिता शाहजी भोंसले के वीरतापूर्ण जीवन ने उन्हें साहस और कर्तव्यनिष्ठा का मार्ग दिखाया। इन पारिवारिक संस्कारों ने उनके व्यक्तित्व में धार्मिक उदारता और मानवीय संवेदना की मजबूत नींव रखी।

जयंती पर विशेष

डॉ. रामेश्वर मिश्र

लेखक समाजसेवी हैं।

'शिवाजी और धार्मिक सहिष्णुता का संदेश' भारतीय इतिहास की उस प्रेरक परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें शक्ति और सहिष्णुता का अद्वितीय संतुलन दिखाई देता है। 17वीं शताब्दी का भारत राजनीतिक अस्थिरता, साम्राज्यवादी विस्तार और धार्मिक संघर्षों से जूझ रहा था। ऐसे समय में छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय केवल एक वीर योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे शासक के रूप में हुआ जिसने अपने शासन और आचरण के माध्यम से धार्मिक सहिष्णुता, न्याय और मानवता के उच्च आदर्श स्थापित किए। उनका व्यक्तित्व यह सिद्ध करता है कि सच्चा राष्ट्र निर्माण विविधता के सम्मान और सह-अस्तित्व की भावना पर आधारित होता है।

शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 को महाराष्ट्र के दुर्गम और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शिवनेरी किला में हुआ था। इसलिए 19 फरवरी को उनकी जयंती बड़े सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। यह दिन केवल एक ऐतिहासिक स्मृति नहीं, बल्कि भारतीय समाज के लिए राष्ट्र गौरव, स्वाभिमान और सहिष्णुता के मूल्यों को पुनः स्मरण करने का अवसर भी है। उनकी माता जीजाबाई ने बचपन से ही उनमें धर्म, नीति, करुणा और न्याय के संस्कारों का रोपण किया, जबकि पिता शाहजी भोंसले के वीरतापूर्ण जीवन ने उन्हें साहस और कर्तव्यनिष्ठा का मार्ग दिखाया। इन पारिवारिक संस्कारों ने उनके व्यक्तित्व में धार्मिक उदारता और मानवीय संवेदना की मजबूत नींव रखी।

शिवाजी का दृष्टिकोण अपने समय की संकीर्ण धार्मिक राजनीति से भिन्न था। उन्होंने धर्म को राज्यसत्ता का साधन नहीं बनाया, बल्कि उसे व्यक्तिगत आस्था और नैतिकता का विषय माना। उनके लिए शासन का मूल उद्देश्य जनकल्याण, न्याय और सुरक्षा था। यही कारण है कि उनके राज्य में विभिन्न धर्मों के लोग समान सम्मान के साथ रहते थे और प्रशासन में सक्रिय भागीदारी निभाते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि एक आदर्श राज्य वही है जहाँ सभी समुदाय अपने धार्मिक विश्वासों के साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें।

शिवाजी की धार्मिक सहिष्णुता का सबसे प्रभावी प्रमाण उनके सैन्य अभियानों में मिलता है। उस समय युद्धों के दौरान धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुँचाना सामान्य बात मानी जाती थी, परन्तु शिवाजी ने इस प्रवृत्ति का सख्ती से विरोध किया। उन्होंने अपने सैनिकों को स्पष्ट आदेश दिया कि किसी भी मस्जिद, दरगाह या अन्य पवित्र स्थल को क्षति न पहुँचाई जाए। यह दृष्टिकोण उनके उच्च मानवीय आदर्शों का प्रतीक था। वे मानते थे कि धर्म का वास्तविक स्वरूप मानवता, करुणा और सद्भाव में निहित है, न कि वैमनस्य और विभाजन में।

शिवाजी की धार्मिक नीति केवल सिद्धांतों तक सीमित नहीं थी, बल्कि व्यवहार में भी उतनी ही स्पष्ट दिखाई देती थी। उनके प्रशासन और सेना में विभिन्न धर्मों के लोग उच्च पदों पर नियुक्त थे। कई मुस्लिम अधिकारी उनके विश्वसनीय सेनापति और कूटनीतिज्ञ के रूप में कार्यरत थे। यह तथ्य इस बात का प्रमाण है कि शिवाजी के लिए व्यक्ति की पहचान उसके धर्म से नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और निष्ठा से निर्धारित होती थी। यह दृष्टिकोण उस युग के लिए अत्यंत प्रगतिशील था और आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों की झलक प्रस्तुत करता है।

उनके समय में मुगल साम्राज्य का प्रभाव बढ़ रहा था और धार्मिक नीतियों को लेकर अनेक प्रकार के तनाव उत्पन्न हो रहे थे। विशेषतः औरंगज़ेब की नीतियों के कारण धार्मिक असहिष्णुता का वातावरण निर्मित हुआ। ऐसे दौर में शिवाजी का उदार और संतुलित दृष्टिकोण अत्यंत महत्वपूर्ण था। उन्होंने संघर्ष अवश्य किया, परन्तु वह किसी धर्म विशेष के विरुद्ध नहीं, बल्कि राजनीतिक स्वाधीनता और जनसम्मान की रक्षा के लिए था। उनके संघर्ष का उद्देश्य सत्ता प्राप्ति मात्र नहीं, बल्कि समाज में न्याय और सम्मान की स्थापना था।

शिवाजी का जीवन यह स्पष्ट करता है कि धार्मिक सहिष्णुता का अर्थ अपने धर्म से विमुख होना नहीं, बल्कि अन्य धर्मों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता रखना है। वे अपनी आस्था में दृढ़ थे, परन्तु उन्होंने कभी भी अन्य धर्मों का अपमान नहीं किया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि एक सशक्त शासक वही है जो अपनी प्रजा की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करे और सभी समुदायों के अधिकारों को समान रूप से महत्व दे। उनके शासन में किसी भी प्रकार की धार्मिक कट्टरता या भेदभाव को स्थान नहीं दिया गया, जिससे सामाजिक सौहार्द्र और विश्वास की भावना मजबूत हुई।

उनकी धार्मिक नीति में मानवीय मूल्यों की गहरी छाप दिखाई देती है। महिलाओं के सम्मान, निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा और धार्मिक स्थलों की रक्षा जैसे सिद्धांत उनके शासन के मूल आधार थे। युद्ध के समय भी उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि आम जनता और धार्मिक संस्थानों को कोई नुकसान न पहुँचे। यह दृष्टिकोण केवल राजनीतिक विवेक का परिणाम नहीं था, बल्कि उनके भीतर निहित मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक था। उन्होंने यह दिखाया कि सच्चा पराक्रम केवल युद्ध में विजय प्राप्त करने में नहीं, बल्कि मानवता की रक्षा करने में निहित होता है।

शिवाजी की सांस्कृतिक दृष्टि भी उनकी धार्मिक सहिष्णुता को पुष्ट करती है। वे भारतीय संस्कृति की विविधता को उसकी शक्ति मानते थे और विभिन्न परंपराओं तथा रीति-रिवाजों को सम्मान देते थे। उनके राज्य में हिंदू, मुस्लिम और अन्य समुदायों के लोग अपने-अपने धार्मिक अनुष्ठान स्वतंत्र रूप से कर सकते थे। यह वातावरण सामाजिक समरसता और पारस्परिक विश्वास को बढ़ावा देता था, जो किसी भी सुदृढ़ राष्ट्र के निर्माण के लिए अनिवार्य होता है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि विविधता में एकता केवल एक आदर्श वाक्य नहीं, बल्कि शासन की व्यावहारिक नीति भी हो सकती है।

आज के संदर्भ में शिवाजी का यह संदेश अत्यंत प्रासंगिक प्रतीत होता है। जब समाज में वैचारिक और धार्मिक विभाजन की प्रवृत्तियाँ उभरती हैं, तब शिवाजी का आदर्श हमें सह-अस्तित्व, सम्मान और संवाद का मार्ग दिखाता है। उनका जीवन यह सिखाता है कि धर्म के नाम पर संघर्ष नहीं, बल्कि सहयोग और समन्वय का वातावरण बनाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी सांस्कृतिक और धार्मिक समरसता में निहित होती है, न कि किसी एक धर्म के वर्चस्व में।

19 फरवरी को मनाई जाने वाली उनकी जयंती हमें केवल उनके वीरतापूर्ण कारनामों की याद नहीं दिलाती, बल्कि उनके मानवीय और उदार शासन दृष्टिकोण को भी स्मरण कराती है। यह दिन हमें यह सोचने का अवसर देता है कि आज के समाज में हम किस प्रकार सहिष्णुता, न्याय और समानता के मूल्यों को सुदृढ़ कर सकते हैं। शिवाजी का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने धार्मिक विश्वासों के साथ-साथ दूसरों की आस्थाओं का भी सम्मान करें और समाज में सौहार्द्र तथा विश्वास का वातावरण बनाए रखें।

इस प्रकार, शिवाजी का व्यक्तित्व धार्मिक सहिष्णुता, मानवीय संवेदना और न्यायपूर्ण शासन का अद्वितीय उदाहरण है। उन्होंने अपने आचरण से यह सिद्ध किया कि शक्ति और सहिष्णुता एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकते हैं। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था, क्योंकि समाज की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब विविध आस्थाओं के बीच सम्मान और विश्वास का सेतु निर्मित हो। शिवाजी का आदर्श हमें यह प्रेरणा देता है कि हम एक ऐसे भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ें जहाँ धर्म, संस्कृति और विचारों की विविधता के बीच भी एकता, न्याय और सहिष्णुता सर्वोपरि हों।

शिवाजी को अपनी अपराजेयता पर अटूट विश्वास था

जयंती पर विशेष

डॉ. मुरलीधर चाँदनीवाला

लेखक शिक्षाविद है।

छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का महान् चरित्र अब अतीत का विषय नहीं रह गया है। शिवाजी महाराज का इतिहास-विमर्श करने की अपेक्षा अब उन बिन्दुओं पर आना चाहिए कि वे कौन-कौन सी बातें थी, जिनका सकारात्मक प्रभाव हिन्दू समाज पर पड़ा। हिन्दुओं के साथ-साथ समूचे राष्ट्र के पुनर्जागरण की शुरुआत तो शिवाजी के युग से ही मानी जानी चाहिए। वह शिवाजी महाराज का ही विराट स्वप्न था, जो उनके जीवित रहते हुए साकार हुआ। बाद की सामरिक परिस्थितियाँ जो भी रही हों, शिवाजी का स्वप्न अंत तक हिन्दू समाज की आँखों में झिलमिल करता रहा। हिन्दू वीरों की भुजाओं में जो लोहा दिखाई देता रहा, वह शिवाजी महाराज की टकसाल से ही ढलकर आया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम छोर तक सेनानियों में शिवाजी का शौर्य, उत्साह, बलिदान, वीरोचित उत्तेजना और तीव्रतम ललकार दिखाई देती रही। मराठों के अभेद्य दुर्गों से निकलकर युद्ध की जो तलवारें पूरे भारत में लहराने लगीं, वे सब शिवाजी महाराज की भवानी तलवार की ही वंशजाएँ थीं।

मध्यकालीन भारत के इतिहास में शिवाजी महाराज जैसा प्रगतिशील और त्रिकालदर्शी सम्राट दूसरा नहीं हुआ। विधर्मियों की बड़ी भारी सेनाओं और उनके कुटिल सेनापतियों को अपने सामने आक्रामक मुद्रा में खड़ा हुआ देखकर भी अपने भीतर हीनता का विचार लाये बिना किस तरह युद्ध जीता जा सकता है, इसके लिये शिवाजी महाराज के द्वारा अपने गये तरीके मौलिक थे। वे इससे पहले कभी नहीं अपनाये गये थे, लेकिन शिवाजी महाराज को अपनी अपराजेयता पर अटूट विश्वास था। यह विश्वास यूँ ही नहीं था, यह उन आदर्शों पर विश्वास था, जो उन्होंने रघुकुल के राजाओं में देखा था। समरांगण में श्रीराम उनके सच्चे आदर्श थे। वे अनुभव करते थे कि उनकी ओर से श्रीराम ही युद्ध लड़ रहे हैं। शिवाजी महाराज के खाते में जितनी भी विजय-गाथाएँ हैं, वे श्रीराम की हैं, उदात्त चरित्र की हैं, हिन्दुओं के स्वाभिमान की हैं।

शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की स्थापना के साथ ही साथ धार्मिक सहिष्णुता के बीज बो दिये थे, जो उनके समय के देश और परिस्थिति में बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। उन्होंने ब्राह्मणों के पुरातन गौरव की रक्षा ही नहीं की, अपितु उनकी कार्य-संस्कृति को जगाये रखने के लिये उल्लेखनीय प्रयास किये। ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रयास थे, जो शिवाजी महाराज से पहले और बाद में भी कम ही दिखाई देते हैं। शिवाजी महाराज जानते थे कि हिन्दू संस्कृति को पालने-पोसने का महत्त्व दायित्व युगों-युगों से ब्राह्मण-कुल ही करते चले आये हैं। शिवाजी महाराज ने वेदों के पठन-पाठन और उनके अनुशीलन की नई संरचना बनाई, और उसे क्रियान्वित भी किया। शिवाजी महाराज को मराठों के त्याग और बलिदान पर पक्का भरोसा था। इसी भरोसे ने शिवाजी महाराज की सामरिक नीतियों को ताकत दी।

शिवाजी महाराज हिन्दुओं की उदासीन प्रवृत्तियों को लेकर बहुत चिन्तित रहते थे। उनका दृष्टिकोण यह था कि हिन्दू ज्ञानमार्गी रहे, भक्तिकालीन प्रभावों में भी रहे, लेकिन अपनी क्षत्रियोचित महिमा पर धूल न जमने दे। वे रामराज्य वाली श्रीराम की मर्यादा का भी सम्मान करते थे, लेकिन आततायियों के विरुद्ध शिव के अमोघ त्रिशूल को भी हिन्दू संस्कृति का उच्चतम प्रहरी मानते थे। दमित और शोषित लोगों में, जड़ता और अंधकार से घिरे हुए परिवारों में, भोग-विलास में लिप्त हो चुके युवाओं में, दबी-कुचली हिन्दू प्रजा में शिवाजी महाराज ने प्राण फूँक कर उन्हें उठ खड़ा होने का हौंसला दिया। इसीलिये वे हिन्दुस्तान के भाग्य-विधाता समझे जाते हैं। बहुधा कहा जाता है कि यदि शिवाजी महाराज इस धरा पर नहीं आते तो विश्व के मानचित्र पर पूरा भारत सदियों पीछे छूट जाता और हिन्दू समाज को अपने लिये कोई राह दिखाई नहीं देती।

शिवाजी महाराज को बहुत लम्बा जीवन नहीं मिला। पचास वर्ष की आयु में सिमटा हुआ उनका जीवन बाद के हिन्दू नरेशों के लिये महान् आदर्श की तरह रहा है। मुगलों और बीजापुर सल्तनत के विरुद्ध शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध जैसी तकनीक का प्रयोग कर यह साबित किया कि हमेशा ही पारम्परिक युद्ध लड़ा जाना लाभ नहीं, कभी-कभी हानि ही पहुँचाता है। शिवाजी महाराज के द्वारा लड़े गये प्रायः सभी युद्ध गैर-पारंपरिक थे। इतना ही नहीं, उनके सब युद्ध उन अलग-अलग प्रणालियों में हैं, जिनका आविष्कार स्वयं शिवाजी महाराज की अपनी उपज है। इन्हीं प्रणालियों को गूँज कर उन्होंने अनुशासित सेना और न्यायप्रिय नागरिक शासन की मजबूत नींव रखी। आठ मंत्रियों की परिषद् के रूप में 'अष्टप्रधान' की संकल्पना को साकार कर शिवाजी महाराज ने अपने हिन्दवी साम्राज्य को सुदृढ़ किया।

हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला की प्रसिद्ध कविता 'छत्रपति शिवाजी का पत्र' हिन्दुस्तान की चेतना को जगाने के लिये उस ओज और तेज का आह्वान करती है, जो शिवाजी महाराज की अपनी जनता से मांग थी। यह पत्र छत्रपति शिवाजी की ओर से मुगलों के मनसबदार राजा जयसिंह को तो लिखा गया है, लेकिन वास्तव में यह उन सभी को सम्बोधित है, जो राष्ट्रवाद की चेतना को कुचलने का कुत्सित प्रयास करते रहते हैं। निराला की इस कविता की ये पंक्तियाँ हमें आज भी आश्वस्त करती हैं-

आयेगी भाल पर भारत की नई ज्योति,
हिन्दुस्तान मुक्त होगा घोर अपमान से,
दासता के पाश कट जायेंगे।
मिलो राजपूतों से,
घेरो तुम दिल्ली-गढ़,
तब तक मैं दोनों सुल्तानों को देख लूँ।
सेना घटा-घटा सी,
मेरे वीर सरदार घेरेंगे गोलकुण्डा, बीजापुर,
चमकेंगे खड्ग सब विद्युयुति बार-बार,
खून की पियेंगी धार,
संगिनी सहेलियाँ भवानी की,
धन्य हूँगा, देव-द्विज-देश को
सर्वस्व सौंपकर निज।

द्वितीय सरसंघचालक गुरुजी का समग्र दृष्टिकोण

राष्ट्र-चेतना के साधक

डॉ. भूपेन्द्र कुमार सुल्लेरे

भारत के राष्ट्र जीवन में कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो सत्ता, पद और प्रचार से दूर रहकर भी युग की दिशा तय करते हैं। वे समय के शोर में नहीं, बल्कि इतिहास की गहराइयों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। ऐसे ही तपस्वी, विचारक और संगठनकर्ता थे माधव सदाशिव गोलवलकर, जिन्हें राष्ट्र ने श्रद्धा से 'गुरुजी' कहा। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक थे और 1940 से 1973 तक लगभग 33 वर्षों तक संघ का मार्गदर्शन किया। उनका जीवन भारतीय राष्ट्रवाद की सांस्कृतिक व्याख्या का आधारस्तंभ है।

गुरुजी का जन्म 19 फरवरी 1906 को हुआ। बचपन से ही उनमें अध्ययनशीलता, अनुशासन और आत्मसंयम के गुण स्पष्ट दिखाई देते थे। उच्च मेंग शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी उनका जीवन भौतिक उपलब्धियों की ओर नहीं गया, बल्कि आत्मिक साधना और सामाजिक दायित्व की ओर उन्मुख हुआ। वेदांत, उपनिषद, भारतीय दर्शन, इतिहास और संस्कृति का उनका अध्ययन अत्यंत गहरा था। वे आधुनिक शिक्षा से परिचित थे, किंतु उनकी चेतना की जड़ें भारतीय परंपरा में थीं। यही संतुलन उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता थी। गुरुजी का व्यक्तित्व सरल था, पर प्रभाव अत्यंत गहन। वे कम बोलते थे, किंतु उनके शब्द कार्यकर्ताओं के जीवन में दिशा बन जाते थे। उनमें न तो पद का अहंकार था, न प्रसिद्धि की आकांक्षा। उनका जीवन स्वयं एक चलता-फिरता उदाहरण था कि कैसे त्याग, अनुशासन और निरंतर साधना के माध्यम से समाज को दिशा दी जा सकती है।

1940 में जब गुरुजी ने द्वितीय सरसंघचालक का दायित्व संभाला, तब भारत का समय अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। स्वतंत्रता आंदोलन अपने निर्णायक चरण में था, द्वितीय विश्वयुद्ध की छाया थी, वैचारिक भ्रम और राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण था। इसके बाद देश का विभाजन हुआ, जिसने भारतीय समाज की आत्मा को गहरा आघात पहुँचाया। इसी कालखंड में संघ पर प्रतिबंध लगे, कार्यकर्ताओं को कारावास झेलना पड़ा और संगठन पर गंभीर आरोप लगाए गए। ऐसे कठिन समय में गुरुजी ने धैर्य, विवेक और दीर्घकालिक दृष्टि के साथ संघ का नेतृत्व किया।

गुरुजी का 33 वर्ष का सरसंघचालक काल संघ के इतिहास में विस्तार और स्थायित्व का काल माना जाता है। उन्होंने संगठन को भावनात्मक प्रतिक्रिया के मार्ग पर नहीं, बल्कि अनुशासित, विचारपूर्ण और समाजोन्मुख पथ पर आगे बढ़ाया। शाखाओं का देशव्यापी विस्तार हुआ, प्रचारक व्यवस्था सुदृढ़ हुई और संघ एक संगठित सामाजिक शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। गुरुजी का स्पष्ट मत था कि संगठन की वास्तविक शक्ति संख्या में नहीं, बल्कि संस्कार में होती है। इसलिए उन्होंने व्यक्ति-निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रचारक जीवन गुरुजी की सोच का केंद्र था। वे स्वयं प्रचारक थे और प्रचारक को केवल संगठनकर्ता नहीं, बल्कि समाज-शिक्षक मानते थे। उनके अनुसार प्रचारक का जीवन त्याग, सादगी, निरंतर अध्ययन और समाज के साथ जीवंत संवाद का जीवन होता है। उन्होंने प्रचारकों को निर्देश दिया कि वे स्थानीय समाज की भाषा, संस्कृति और संवेदनाओं से जुड़ें। इसी कारण संघ का कार्य किसी एक क्षेत्र, भाषा या वर्ग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संपूर्ण भारत में विविध रूपों में विकसित हुआ।

गुरुजी की दूरदृष्टि का एक महत्वपूर्ण पक्ष विभिन्न अनुषांगिक संगठनों का उदय था। उनका मानना था कि राष्ट्र का पुनर्निर्माण केवल एक संगठन के माध्यम से संभव नहीं है। समाज के हर क्षेत्र–शिक्षा, श्रम, राजनीति, सेवा, जनजातीय जीवन, महिला सशक्तिकरण–में राष्ट्रभाव से प्रेरित कार्य होना चाहिए। इसी सोच के कारण अनेक संगठनों का विकास हुआ, जिन्होंने समाज के विभिन्न आयामों में राष्ट्रवादी चेतना का संचार किया। गुरुजी की राष्ट्र-कल्पना अत्यंत व्यापक और गहरी थी। उनके लिए राष्ट्र केवल एक राजनीतिक इकाई नहीं था, बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक सत्ता थी, जो सहस्राब्दियों से निरंतर प्रवाहित है। वे मानते थे कि भारत की एकता का आधार उसकी सांस्कृतिक समरसता है, न कि केवल संवैधानिक या प्रशासनिक व्यवस्थाएँ। उनका राष्ट्रवाद कर्तव्य, संस्कार और सांस्कृतिक उत्तरदायित्व पर आधारित था। उनके अनुसार व्यक्ति से पहले समाज और समाज से पहले राष्ट्र आता है।

विदेश नीति के प्रश्न पर गुरुजी की दृष्टि अत्यंत यथार्थवादी थी। वे विश्व शांति के समर्थक थे, किंतु राष्ट्र-सुरक्षा के प्रश्न पर किसी भी प्रकार के आदर्शवाद को अव्यावहारिक मानते थे। उन्होंने समय रहते आक्रामक विस्तारवादी प्रवृत्तियों को पहचाना और भारत की सीमाओं की सुरक्षा पर गंभीर चिंता व्यक्त की। उनका स्पष्ट मत था कि भारत को नैतिक शक्ति के साथ-साथ सामरिक रूप से भी सशक्त होना चाहिए। वे मानते थे कि कमजोर राष्ट्र की नैतिक अपील भी प्रभावहीन हो जाती है।

पूर्वोत्तर भारत गुरुजी की दृष्टि में कभी हाशिये का क्षेत्र नहीं रहा। वे इसे भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामरिक सुरक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग मानते थे। उनका विश्वास था कि जनजातीय समाज भारत की मूल सांस्कृतिक चेतना का वाहक है। वे अलगाववाद को केवल राजनीतिक समस्या नहीं, बल्कि संवाद और आत्मीयता की कमी का परिणाम मानते थे। गुरुजी का आग्रह था कि पूर्वोत्तर भारत को समझने के लिए वहां की संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक संरचना का सम्मान आवश्यक है। आज पूर्वोत्तर में जो सांस्कृतिक और वैचारिक जागरण दिखाई देता है, उसकी जड़ें कहीं न कहीं गुरुजी की इसी सोच में निहित हैं।

सामाजिक समरसता गुरुजी के विचारों का केंद्रीय तत्व थी। उनका राष्ट्रवाद समावेशी था। वे समाज के हर वर्ग को राष्ट्र-निर्माण का सहभागी मानते थे। जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर विभाजन को वे राष्ट्र के लिए घातक मानते थे। उनके अनुसार सामाजिक समरसता केवल नारों से नहीं, बल्कि व्यवहार, सेवा और संवेदनशीलता से स्थापित होती है। यही कारण है कि उन्होंने सेवा कार्यों को संघ जीवन का अभिन्न अंग बनाया। आज के वैश्विक परिदृश्य में गुरुजी की वैचारिक विरासत और अधिक प्रासंगिक हो जाती है। जब विकास, शक्ति और राजनीति की दौड़ तेज है, तब वे हमें स्मरण कराते हैं कि बिना सांस्कृतिक जड़ों के विकास खोखला होता है। वे सिखाते हैं कि राष्ट्र का निर्माण तात्कालिक सफलताओं से नहीं, बल्कि दीर्घकालिक संस्कारों से होता है।

उपसंहार के रूप में कहा जा सकता है कि द्वितीय सरसंघचालक गुरुजी भारतीय राष्ट्रवाद के सांस्कृतिक शिल्पकार थे। उनका जीवन त्याग, विचार और संगठन की त्रिवेणी है। 19 फरवरी उनकी जन्म-जयंती केवल स्मरण का दिवस नहीं, बल्कि आत्ममंथन और संकल्प का अवसर है। गुरुजी आज भी हमें यह सिखाते हैं कि राष्ट्र-सेवा कोई घटना नहीं, बल्कि एक सतत साधना है। भारतीय समाज की आत्मा को गहरा आघात पहुँचाया। इसी कालखंड में संघ पर प्रतिबंध लगे, कार्यकर्ताओं को कारावास झेलना पड़ा और संगठन पर गंभीर आरोप लगाए गए। ऐसे कठिन समय में गुरुजी ने धैर्य, विवेक और दीर्घकालिक दृष्टि के साथ संघ का नेतृत्व किया।

गुरुजी का 33 वर्ष का सरसंघचालक काल संघ के इतिहास में विस्तार और स्थायित्व का काल माना जाता है। उन्होंने संगठन को भावनात्मक प्रतिक्रिया के मार्ग पर नहीं, बल्कि अनुशासित, विचारपूर्ण और समाजोन्मुख पथ पर आगे बढ़ाया। शाखाओं का देशव्यापी विस्तार हुआ, प्रचारक व्यवस्था सुदृढ़ हुई और संघ एक संगठित सामाजिक शक्ति के रूप में स्थापित हुआ। गुरुजी का स्पष्ट मत था कि संगठन की वास्तविक शक्ति संख्या में नहीं, बल्कि संस्कार में होती है। इसलिए उन्होंने व्यक्ति-निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रचारक जीवन गुरुजी की सोच का केंद्र था। वे स्वयं प्रचारक थे और प्रचारक को केवल संगठनकर्ता नहीं, बल्कि समाज-शिक्षक मानते थे। उनके अनुसार प्रचारक का जीवन त्याग, सादगी, निरंतर अध्ययन और समाज के साथ जीवंत संवाद का जीवन होता है। उन्होंने प्रचारकों को निर्देश दिया कि वे स्थानीय समाज की भाषा, संस्कृति और संवेदनाओं से जुड़ें। इसी कारण संघ का कार्य किसी एक क्षेत्र, भाषा या वर्ग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि संपूर्ण भारत में विविध रूपों में विकसित हुआ।

पूर्वोत्तर भारत गुरुजी की दृष्टि में कभी हाशिये का क्षेत्र नहीं रहा। वे इसे भारत की सांस्कृतिक विविधता और सामरिक सुरक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग मानते थे। उनका विश्वास था कि जनजातीय समाज भारत की मूल सांस्कृतिक चेतना का वाहक है। वे अलगाववाद को केवल राजनीतिक समस्या नहीं, बल्कि संवाद और आत्मीयता की कमी का परिणाम मानते थे। गुरुजी का आग्रह था कि पूर्वोत्तर भारत को समझने के लिए वहां की संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक संरचना का सम्मान आवश्यक है। आज पूर्वोत्तर में जो सांस्कृतिक और वैचारिक जागरण दिखाई देता है, उसकी जड़ें कहीं न कहीं गुरुजी की इसी सोच में निहित हैं।

सामाजिक समरसता गुरुजी के विचारों का केंद्रीय तत्व थी। उनका राष्ट्रवाद समावेशी था। वे समाज के हर वर्ग को राष्ट्र-निर्माण का सहभागी मानते थे। जाति, भाषा या क्षेत्र के आधार पर विभाजन को वे राष्ट्र के लिए घातक मानते थे। उनके अनुसार सामाजिक समरसता केवल नारों से नहीं, बल्कि व्यवहार, सेवा और संवेदनशीलता से स्थापित होती है। यही कारण है कि उन्होंने सेवा कार्यों को संघ जीवन का अभिन्न अंग बनाया। आज के वैश्विक परिदृश्य में गुरुजी की वैचारिक विरासत और अधिक प्रासंगिक हो जाती है। जब विकास, शक्ति और राजनीति की दौड़ तेज है, तब वे हमें स्मरण कराते हैं कि बिना सांस्कृतिक जड़ों के विकास खोखला होता है। वे सिखाते हैं कि राष्ट्र का निर्माण तात्कालिक सफलताओं से नहीं, बल्कि दीर्घकालिक संस्कारों से होता है।

द्वितीय सरसंघचालक गुरुजी भारतीय राष्ट्रवाद के सांस्कृतिक शिल्पकार थे। उनका जीवन त्याग, विचार और संगठन की त्रिवेणी है। 19 फरवरी उनकी जन्म-जयंती केवल स्मरण का दिवस नहीं, बल्कि आत्ममंथन और संकल्प का अवसर है। गुरुजी आज भी हमें यह सिखाते हैं कि राष्ट्र-सेवा कोई घटना नहीं, बल्कि एक सतत साधना है।

निर्धारित समय पर पूर्ण करें समर्पण निधि का लक्ष्य: सुधाकर पंवार

आजीवन सहयोग निधि एवं आगामी कार्यक्रम को लेकर जिले की बैठक संपन्न

बैतूल। जिला भाजपा कार्यालय विजय भवन में आयोजित आजीवन सहयोग निधि एवं अन्य आगामी कार्यक्रमों को लेकर कामकाजी बैठक संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पंवार ने कहा कि अब मंडल स्तर पर अध्यक्ष प्रभारी एवं सह प्रभारी हमारे त्रिदेव की भूमिका में है। तीनो मिलकर बूथ स्तर तक प्रवास करें एवं पार्टी के लक्ष्य को समय पर पूर्ण करें। जिलाध्यक्ष श्री पंवार ने कहा कि पार्टी के सभी कार्यक्रम को हमारे कार्यकर्ता उत्साह पूर्वक संपन्न करते है। भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित दल है एवं कार्यकर्ताओं के सहयोग से पार्टी की सभी गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित होती है। हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता यही हमारी पार्टी की कार्यपद्धति है। आगामी कार्यक्रम मन की बात कार्यक्रम 22 फरवरी को संपन्न होना है।

जिसको लेकर कार्ययोजना बना ले एवं हर बूथ पर कार्यक्रम संपन्न करें। बजट का प्रचार प्रसार एवं वीबी जी राम जी के कार्यक्रम सफलता पूर्वक संपन्न होने पर जिलाध्यक्ष श्री पंवार ने सभी मंडल अध्यक्षो को बधाई दी। उन्होने कहा कि आगामी समय में पं.दीनदयाल उपाध्याय महा प्रशिक्षण अभियान के कार्यक्रम होने है मंडल स्तर पर मंडल अध्यक्ष एवं प्रभारी मिलकर आगामी कार्यक्रम की कार्ययोजना तैयार करें। बैठक को संबोधित करते हुए आजीवन सहयोग निधि के जिला प्रभारी दीपक सलूजा ने आजीवन सहयोग निधि संग्रहण को लेकर तकनीकि बाते सुक्ष्मता से साझा करते हुए कहा कि इस बार नगद राशि का कोई प्रावधान नही है। चेक के माध्यम से ही आजीवन निधि प्राप्त करना है। जिले के सभी 30 मंडलो में कार्य विभाजन कर राशि संग्रहण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। जिले का लक्ष्य तय तारीख से पहले हासिल करने के लिए हमें आज से जुट जाना है। बैठक को संबोधित करते हुए जिला महामंत्री कमलेश सिंह ने कहा कि पिछले सभी अभियान और कार्यक्रम हमने सफलता पूर्वक संपन्न किए है बजट 2026 के प्रचार प्रसार के कार्यक्रम सभी मंडलो में संपन्न हुए। विकास खंड स्तर पर वीबी जी राम जी अभियान के कार्यक्रम संख्यात्कम रूप से प्रभावशाली रहे है। और अब आजीवन सहयोग निधि संग्रहण में हमे पिछले वर्ष के लक्ष्य से आगे निकलते हुए नया आयाम स्थापित करना है। आगामी दिनों मे कार्यकर्ताओ के प्रशिक्षण का कार्य मंडल स्तर पर होना है जिसको लेकर जिला एवं मंडल स्तर पर टोली का गठन हो चुका है। बैठक का संचालन आजीवन सहयोग निधि के सह संयोजक प्रशांत गावंडे ने एवं अंत में आभार अभियान के जिला सह संयोजक महेश्वर सिंह चंदेल ने व्यक्त किया। इस दौरान जिला महामंत्री कृष्णा गायकी, डा.महेन्द्र सिंह चौहान मंचासीन रहे। बैठक में मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, आजीवन सहयोग निधि अभियान के मंडल संयोजक, सह संयोजक उपस्थित रहे।

पुलिस ग्राउंड में आज मप्र पुलिस महिला प्री ट्रायल चैंपियनशिप

सुपर 50 बेटियों को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाणपत्र से किया जाएगा सम्मानित

बैतूल। मेरा वतन वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में आज 19 फरवरी को सुबह 7 बजे से पुलिस ग्राउंड बैतूल में मप्र पुलिस महिला वर्ग चैंपियनशिप प्री ट्रायल 2026 का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन मप्र पुलिस की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर चुकी बेटियों के लिए विशेष रूप से किया जा रहा है, ताकि वे फिजिकल ट्रायल से पहले अपने प्रदर्शन को परख सकें और सुधार सकें। प्रतियोगिता में 800 मीटर दौड़, शॉट पुट और लॉन्ग जम्प की स्पर्धाएं होंगी। इन तीनों इवेंट्स में संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर चैंपियन का चयन किया जाएगा। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभागी को 2100 रुपये और चैंपियन ट्रॉफी, द्वितीय स्थान को 1100 रुपये और ट्रॉफी, तृतीय स्थान को 701 रुपये और ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। चौथे से दसवें स्थान तक 500, 400, 300, 300, 300, 300 और 300 रुपये की पुरस्कार राशि के साथ ट्रॉफी और प्रमाणपत्र दिए जाएंगे। सुपर 50 बेटियों में प्रथम से दसवें स्थान तक ट्रॉफी और प्रमाणपत्र तथा 11 से 50 स्थान तक मेडल और स्कोर सहित प्रमाणपत्र प्रदान किए जाएंगे। आयोजन पूर्णत- निःशुल्क रहेगा और इसमें मप्र पुलिस फिजिकल जैसा वास्तविक माहौल तैयार किया जाएगा, जिससे प्रतिभागियों को आत्मविश्वास बढ़ाने का अवसर मिलेगा। आयोजन में फौजी अशोक रघुवंशी, निःशुल्क फिजिकल क्लब आरडीए और आर ए स्पोर्ट्स बैतूल की प्रमुख भूमिका रहेगी। सहयोगी संस्थाओं में महेश सोनी पूर्व सैनिक निःशुल्क फिजिकल क्लब, कमांडो फिजिकल अकादमी और बैतूल फिजिकल अकादमी शामिल हैं। आयोजकों ने सभी पात्र बेटियों से समय पर पहुंचकर अपने सपनों की वर्दी की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाने का आह्वान किया है।

85 दुकानदारों को विस्थापित करने आवंटित किए हैं भूखंड, बिजली-सड़क जैसी सुविधाएं नदारद

39 टीनशेड दुकानों में से खुल रही सिर्फ चार दुकानें

बैतूल। अभिनंदन सरोवर के पीछे नगरपालिका ने 85 दुकानदारों को विस्थापित करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया था। इस प्रोजेक्ट को आनन-फानन में पूरा करने के लिए 39 दुकानें बना दी। लेकिन इन दुकानों में अब तक बिजली और सामने सडक़ तक नहीं बनी है। यहां पीने के पानी के इंतजाम के नाम पर एक नल कनेक्शन है। यहीं वजह है कि 39 में से केवल 4 दुकानें ही यहां चालू की हैं। बता दे कि 21 साल पहले अभिनंदन सरोवर के पीछे नगरपालिका ने 85 दुकानदारों को विस्थापित कर दुकानें लगाने भूखंड आवंटित किये थे। करीब दो-तीन महीने पहले ही में यहां 39 टीन शेड की दुकानें बनी है। लेकिन यहां न तो बिजली की व्यवस्था हुई है, न ही सडक और पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। बिजली व्यवस्था न होने से दुकानदार अब भी सडक किनारे अतिक्रमण कर दुकानें चला रहे हैं। इनमें से अधिकांश दुकानदारों का व्यवसाय बिजली पर आधारित है। ऐसे में बिना बिजली उनकी दुकानें चल पाना संभव नहीं है। कई दुकानदारों ने अपने खर्च पर टीनशेड डालकर दुकानें तैयार भी कर ली हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में उन्हें शुरू नहीं कर पा रहे हैं। जानकारी के अनुसार, यह वही 85 दुकानदार हैं, जिनसे वर्ष 2005 में नगरपालिका ने विस्थापन के नाम पर 5-5 हजार रुपए जमा कराए थे। करीब 21 साल बाद इनका पुनर्वास तो किया गया, लेकिन अधूरे प्रबंधन की वजह से वह

अब भी स्थायी ठौर से वंचित हैं।

दुकानें बनवाने विधायक ने दी थी सहायता राशि- स्थानीय विधायक द्वारा इन दुकानदारों को सहायता राशि भी दी गई थी, ताकि वे एक जैसी दुकानें बनवा सकें। कुछ दुकानदारों ने यहां टीनशेड से दुकानों का निर्माण तो कर लिया है, लेकिन सुविधाओं के अभाव के कारण दुकानों का संचालन शुरू नहीं कर पा रहे है। दुकानदारों का कहना है कि नगरपालिका ने दुकानदारों को विस्थापित करने के लिए भूखंड तो आवंटित कर दिये, लेकिन अन्य सुविधाएं अभी तक उपलब्ध नहीं कराई है। सुविधाओं के अभाव में न दुकानदार दुकानें शुरू कर पा रहे है और न ही ग्राहक आ रहे है। इसी वजह से टीनशेड की दुकानें बनाने के बावजूद दुकानों का संचालन शुरू नहीं कर पा रहे है। दुकानदारों का कहना है कि नगरपालिका अधिकारियों से सुविधाओं को लेकर चर्चा की जाती है तो वह आश्वासन देकर दुकानदारों की मांगों को टाल जाते है। ऐसे में सुविधाओं के अभाव में यहां दुकानों का संचालन कर पाना मुश्किल हो रहा है। सभी दुकानें नहीं खुलने के कारण यह मार्केट सूना नजर आता है। जिसके कारण ग्राहक भी बहुत कम संख्या में पहुंच रहे है। जिससे ग्राहकी नहीं हो रही है, इसलिए उन्हें पुरानी दुकान से ही अपना व्यवसाय चलाना पड़ रहा है।

बिजली नहीं होने से दुकानदार परेशान- अभिनंदन सरोवर के पीछे नगरपालिका ने 85 दुकानदारों को विस्थापित कर दुकानें लगाने भूखंड आवंटित किये है। लेकिन बिजली कनेक्शन के लिए अभी तक ट्रांसफार्मर, पोल और लाइन बिछाने का काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। सडक़ को लेकर अभी तक नपा द्वारा कोई ठोस योजना नहीं बनाई है। दुकानदारों का कहना है कि अभिनंदन सरोवर के पीछे नई दुकान अलॉट हो गई, लेकिन वे अपनी पुरानी दुकान में ही व्यापार कर रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि बिजली तो फिलहाल नहीं है। लेकिन हमें यहां दुकान में बैठने के नगरपालिका से निर्देश मिले थे इस कारण हमने यहां पर काम शुरू करवा दिया है। जल्द इंतजाम करवाने ट्रांसफार्मर लगवाने संबंधी आश्वासन दिया गया है। पेवर ब्लॉक भी जल्द लगने वाले हैं।

शाम होते ही करनी पड़ती है दुकानें बंद

अभिनंदन सरोवर के पीछे 39 टीनशेड की दुकानें बनी है। इसमें से चार-पांच ही दुकानें खुल रही है। यह दुकानें भी दिन में खुली रहती है और शाम होते ही दुकानें बंद करनी पड़ती है। दुकानदारों ने बताया कि बिजली की व्यवस्था नहीं होने की वजह से शाम के समय अंधेरा छा जाता है। मोमबत्ती या एमरजेंसी लाइट चार्ज करके लाते है, तो वह भी दो घंटे ही चल पाता है। सुविधाएं नहीं होने के वजह से अपेक्षाकृत ग्राहक भी नहीं आ रहे है। ऊपर से शाम होते ही अंधेरा होने के कारण दुकानें बंद करनी पड़ती है। दुकानदारों का कहना है कि यदि नगरपालिका यहां सुविधाएं उपलब्ध कराये तो सभी दुकानें खुलने लगेगी, जिससे यहां मार्केट जैसा माहौल रहेगा और ग्राहक भी पहुंचेगे, लेकिन सुविधाएं कब तक मिलेगी, यह पता नही है।

सड़क किनारे लगा रहे दुकानें

भूखंड आवंटित और दुकानें बनाने के बाद भी दुकानदार सडक़ किनारे अस्थाई रूप से दुकानें लगा रहे है। जिससे शहर की सडकों पर अतिक्रमण तो नजर आता ही है, साथ ही सडकों की चौड़ाई प्रभावित होने से बार-बार जाम और दुर्घटनाओं का अंदेशा भी बना रहता है। सबसे खराब स्थिति साप्ताहिक बाजार वाले दिन निर्मित होती है, जब अस्थाई दुकानदारों के अलावा सब्जी बाजार में दुकान लगाने वाले विक्रेता आते है। इससे व्यवस्थाएं पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाती है। साप्ताहिक बाजार वाले दिन तो हालात इतने खराब हो जाते है कि लोगों को घंटो जाम में फंसे रहना पड़ता है।

इनका कहना है-

अभिनंदन सरोवर के पीछे जो दुकानें बनाई हैं, उनमें जल्द बिजली के इंतजाम करने ट्रांसफार्मर लगाया जाना हैं। इसके लिए हमें पांच लाख रूपये जमा करवाने है। जल्द ही राशि जमा करवा देगे। यहां पेवर ब्लाक भी लगा दिए जाएंगे।

- सतीश मटसेनिया,
सीएमओ, नगर पालिका बैतूल

सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने 28 अधिकारियों को दिए कारण बताओ नोटिस

संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो कटेगा वेतन

बैतूल। बैतूल कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण में लापरवाही सामने आने पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने समीक्षा बैठक में समय-सीमा के भीतर शिकायतें अटेंड नहीं करने पर जिले के 28 अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों के वेतन से कटौती की जाएगी। सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही पर ऊर्जा विभाग के सहायक प्रबंधक सीएल साकोम, सहायक प्रबंधक यवन कुमार उइके, सहायक प्रबंधक क्षितिज मरावी, सहायक प्रबंधक मनोज इनवाती, सहायक प्रबंधक योगेश अहिरकर, विजय गुजरे, जेई दीपक सोलंकी, सहा-प्रबंधक श्री नितिन आसरेकर, सहा- प्रबंधक राकेश पवार, प्रबंधक श्रीमती दीपशिखा इनवाती, सहा-प्रबंधक संतोष कुमार चंदेल को नोटिस जारी किया है। इसी प्रकार किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी खाद्य ललित लहरपुरे, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आशीष कुमार कुमरे, नगरीय विकास एवं आवास विभाग सीएमओ अरुण श्रीवास्तव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैतूल शिवानी राय, महिला एवं बाल विकास विभाग सीडीपीओ प्रभारी गीता मालवीय, सीडीपीओ संगीता धुर्वे, राजस्व विभाग तहसीलदार शाहपुर टी. विस्के, तहसीलदार प्रभातपट्टन यशवंत सिंह गिन्नारे, तहसीलदार मुलताई संजय बरैया, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग औषधि निरीक्षक संजीव जादौन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत प्रभात पट्टन आंचल पवार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तीजा पवार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भैंसदेही रितेश चौहान, जनपद पंचायत प्रभात पट्टन आंचल पवार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत मुलताई धर्मपाल सिंह मशराम तथा श्रम पदाधिकारी धम्मदीप भगत शामिल है।

आरडी कोचिंग के विद्यार्थियों ने जेईई मैंस में हासिल की उत्कृष्ट सफलता

99.68 परसेंटाइल हासिल कर सजील सूर्यवंशी बने जिले के टॉपर

बैतूल । जिले के उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान में शुमार आर डी कोचिंग क्लासेस बैतूल के विद्यार्थियों ने जेईई मेंस परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता हासिल की है। संस्थान की मेधावी छात्र सजील सूर्यवंशी ने 99.68 परसेंटाइल हासिल कर जिले के टॉपर तथा वेंदांत कास्लेकर 99.25 परसेंटाइल लेकर दूसरे स्थान पर एवं वेदांश साहू 99.00 परसेंटाईल प्राप्त कर संस्थान ही नहीं बल्कि समूचे जिले को गौरवान्वित किया है । जे ई ई मैंस के घोषित परीक्षा परिणाम में आर डी कोचिंग के आधा सैकड़ा से अधिक विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है। इनमें से 25 छात्र - छात्राओं ने 90 परसेंटाइल से अधिक अंक हासिल कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जेईई मेंस परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता हासिल करने वाले आर डी कोचिंग के छात्र- छात्राओं को संस्थान की निदेशक श्रीमती ऋचु खंडेलवाल ने बधाई देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है ।संस्थान में आयोजित गरिमामय सम्मान समारोह में उत्कृष्ट सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निदेशक श्रीमती ऋचु खंडेलवाल ने कहा कि जे ई ई मैंस में मिली शानदार सफलता विद्यार्थियों द्वारा अनुशासन में रहकर किए गए नियमित अभ्यास ,कठोर परिश्रम एवं शिक्षकों के समर्पित मार्गदर्शन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों द्वारा लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने से सफलता निश्चित रूप से मिलती है ।

संस्थान की सुनियोजित शैक्षणिक प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका

आरडी कोचिंग संस्थान की डायरेक्टर श्रीमती खंडेलवाल ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए संस्थान द्वारा अपनाई गई सुनियोजित शिक्षक प्रणाली की भी जे ई ई मैंस के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम में महत्वपूर्ण भूमिका है ।उन्होंने कहा कि संस्थान के विषय विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को नियमित रूप से टेस्ट सीरीज का अभ्यास,कॉन्सेप्ट आधारित अध्यापन, व्यक्तिगत मार्गदर्शन देने के साथ ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पारंगत किया जाता है। उन्होंने कहा कि जे ई ई मैंस के शानदार परिणाम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आर डी कोचिंग क्लासेज के अनुशासित माहौल, गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन एवं लक्ष्य आधारित सतत अभ्यास से ही उत्कृष्ट परिणाम हासिल किया जा सकता है। संस्थान की निदेशक , प्रबंधन एवं प्राचार्य द्वारा उत्कृष्ट सफलता हासिल करने वाले विद्यार्थियों, उनके पालकों और शिक्षकों को बधाई दी तथा जेईई एडवांस सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी समर्पण भाव से करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित किया।

आज दीपों की रोशनी से जगमगाएगा शिवाजी चौक

बैतूल। वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती की तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। इस संबंध में आयोजक व वरिष्ठ समाजसेवी बीआर खंडागरे ने बताया कि गुरुवार को शिवाजी चौक पर शाम 6 बजे शिवाजी महाराज की प्रतिमा के समक्ष हजारों दीपों की रोशनी कर एवं पुष्प वर्षा कर शिवाजी महाराज का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा।

जनगणना 2027 जिला स्तरीय दो दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

जनगणना कार्य में संवेदनशीलता के साथ संम्पूर्ण प्रक्रिया का अनुसरण करे अमला : कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना

हीरालाल गोलानी सोहागपुर

कलेक्टर कार्यालय नर्मदापुरम के सभा कक्ष में जनगणना 2027 के दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण सत्र आज समापन कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के आतिथ्य में संपन्न हुआ। दो दिवसीय प्रशिक्षण में जनगणना 2027 के तैयार पोर्टल की विधिवत जानकारी प्रदान करके अधिकारियों को कराया गया। प्रशिक्षण के द्वितीय दिवस अधिकारियों को जनगणना के तैयार सेंसस मैनेजमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम के संबंध में वास्तविक रूप से व्यावहारिक प्रस्तुति से अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इस ट्रेनिंग मैनेजमेंट, एचएलओ मैनेजमेंट, पोर्टल तथा पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न मॉड्यूल संबंध में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण कर्ता अधिकारियों ने जिले के समस्त अनुविभागीय जनगणना अधिकारी, चार्ज जनगणना अधिकारी तहसीलदार, मुख्य नगरपालिका अधिकारी,चार्ज जनगणना अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी को पोर्टल के उपयोग एवं पोर्टल पर उपलब्ध विभिन्न संसाधनों के उपयोग के अलावा चार्ज अधिकारियों, प्रगणकों की, सुपरवाइजर आदि जनगणना में संलग्न कर्मचारियों के कार्यों की जानकारी दी गई

कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने निर्देशित किया कि जनगणना कार्य के लिए सुपरवाइजर, प्रगणकों सहित अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने हेतु आदेश जारी किए जाएं। वहीं अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के साथ ही उनकी वृहद स्तर पर ट्रेनिंग भी अनुविभागीय जनगणना अधिकारी द्वारा स्वयं की जाए। आपने आगे कहा कि जनगणना से संलग्न कार्यों , तिथियां, नागरिकों के कर्तव्य तथा जानकारी के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया जाए। आपने स्पष्ट निर्देश दिए कि जानकारी एकत्रीकरण करने के समय पर सटीकता का विशेष ध्यान रखा जाए। तथा जनगणना की संपूर्ण कार्यवाही संवेदनशीलता भी बरती जाए। इस दो दिवसीय प्रशिक्षण में अपर कलेक्टर श्री अनिल जैन समस्त अनुविभागीय जनगणना अधिकारी, चार्ज जनगणना अधिकारी तहसीलदार,मुख्य नगरपालिका अधिकारी, चार्ज जनगणना अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी उपस्थित थे।

विक्रमोत्सव 2026

भास रचित संस्कृत नाटक चारुदत्तम् का रंजक मंचन

उज्जैन से डॉ. जफर महमूद

विक्रमोत्सव 2026 के अंतर्गत आयोजित नाट्य महोत्सव में महाकवि भास रचित संस्कृत नाटक 'चारुदत्तम्' का भावपूर्ण मंचन हुआ।

महाराजा विक्रमादित्य शोध पीठ, संस्कृति विभाग मप्र शासन एवं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित विक्रम नाट्य महोत्सव की दूसरी संध्या कालिदास अकादमी में महाराष्ट्र के रामजी बाली के निर्देशन में 'चारुदत्तम' की प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया।महाकवि भास द्वारा रचित 'चारुदत्त' उज्जैन के एक दरिद्र लेकिन ईमानदार ब्राह्मण चारुदत्त और वेश्या वसंतसेना के निश्छल प्रेम पर आधारित है। यह संस्कृत नाट्य परंपरा का प्रसिद्ध नाटक है।

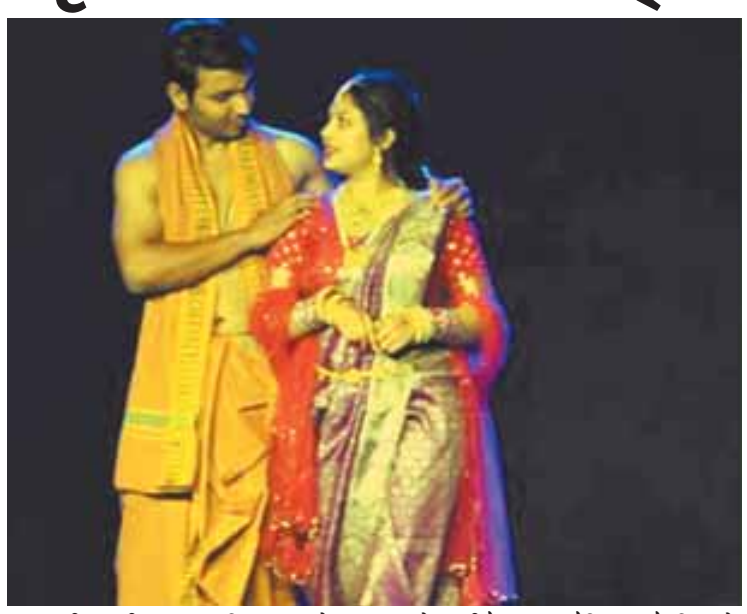

नाटक की कहानी धनाढ्य नायिका वसंतसेना और निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त के प्रेम तथा जीवन-संघर्ष पर आधारित है। वसंतसेना, चारुदत्त के गुणों से प्रभावित होकर उससे प्रेम करने लगती है। चारुदत्त नैतिकता और सिद्धांतों का पालन करने वाला युवा है। नाटक के खलनायक शकार की नायिका पर बुरी नज़र होती है। वह किसी भी तरह उसे पाना चाहता है और इसके लिए झूठ तथा षड्यंत्र का सहारा लेता है। चारुदत्त पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन अंततः सत्य और प्रेम की जीत होती है।

चारुदत्त की कहानी भले ही प्राचीन हो, लेकिन आज के समय में भी उतनी ही प्रासंगिक है। यह युवाओं को महत्वपूर्ण संदेश देती है कि धन आंशिक सम्मान दिला सकता है, लेकिन चरित्र से स्थायी सम्मान प्राप्त होता है। प्रेम स्वार्थरहित होता है और किसी भी परिस्थिति में नैतिकता नहीं छोड़नी चाहिए। ये सभी गुण नायक चारुदत्त में दिखाई देते हैं। वहीं गलत संगति हमेशा नुकसान पहुँचाती है। खलनायक शकार गलत साथियों के कारण गलत निर्णय लेकर स्वयं फँस जाता है। सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सत्य ही विजय होता है। नाटक में सूत्रधार की भूमिका रवि चंद्रा ने निभाई। नायक चारुदत्त की भूमिका में ऋषभ शर्मा, नायिका वसंतसेना के पात्र को अदिति ने प्रभावपूर्ण अभिनय से साकार किया। शाकार की भूमिका सैम सुकांत ने निभाई। आरंभ में नाट्य दल का स्वागत सम्मान सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो अर्पण भारद्वाज एवं समाजसेवी नरेश शर्मा ने किया।

मोहन के विजन पर जगदीश की धनवर्षा

● पहली बार मप्र सरकार का बड़ा व 'ज्ञानी बजट' ● बच्चों, महिलाओं किसानों, कर्मचारियों और आम जनता के लिए खुशखबरी ● टेक्स में राहत, योजनाओं पर रहेगा फोकस ● बजट आकार साढ़े चार लाख करोड़ संभावित ● लाड़ली बहना के लिए 22 हजार करोड़ ● पूंजीगत व्यय 95 हजार करोड़ तक संभव

भोपाल में बुधवार को मध्यप्रदेश का वर्ष 2026-27 का बजट प्रस्तुत किया । बजट में नगर विकास, ग्रामीण क्षेत्र, उद्योग, स्वास्थ्य और कृषि पर विशेष जोर रहा। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था अब सुपरफास्ट ट्रैक पर है। विधानसभा में पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 और बजट से पता चलता है कि पिछले 5 साल प्रदेश के लिए आर्थिक बदलाव के रहे हैं। 2022 में जहां बजट लगभग 2.24 लाख करोड़ रुपये का था, वहीं आज यह 4,38,317 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यानी 5 साल में बजट का आकार करीब 1.60 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य 2029 तक राज्य की अर्थव्यवस्था और बजट को दोगुना करना है।

मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने अपने दूसरे बजट (2025-26) में GYAN यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर जोर दिया था। इससे आगे बढ़कर 2026-27 का बजट GYANII हो गया है, यानी इसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री भी जुड़ गए हैं।

इन छह सेक्टर्स पर ही बजट के 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने हैं। इसमें भी सबसे ज्यादा खर्च इन्फ्रास्ट्रक्चर, किसान और महिलाओं पर होगा।

प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को डॉ. मोहन यादव सरकार का तीसरा बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 का ये बजट 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपए का है। सरकार ने पहली बार रोलिंग बजट पेश किया है यानी इसमें 2026-27 के बजट अनुमान के साथ वित्तीय वर्ष 2027-28 और 2028-29 के बजट का भी अनुमान शामिल है।

वित्त मंत्री के मुताबिक, इससे योजनाओं पर होने वाले खर्च का अनुमान लगाने में मदद मिलेगी। बजट में 50 हजार सरकारी नौकरियों पर भर्तियों का ऐलान किया गया है।

नारी शक्ति

1.27 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान

महिलाओं के लिए इस बजट में 1 लाख 27 हजार 555 करोड़ रुपए के प्रावधान किए गए हैं। वर्किंग वूमन के लिए उज्जैन, धार, रायसेन, भिंड, सिंगरौली, देवास, नर्मदापुरम और झाबुआ में सखी निवास का निर्माण कराया जा रहा है। लाड़ली बहना योजना के लिए 23 हजार 882

करोड़ रुपए दिए गए हैं।

लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 के लिए 1800 करोड़ का प्रावधान है तो यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना शुरू की गई है। इसमें 8वीं क्लास तक के 80 लाख बच्चों को ट्रेटा पैक दूध दिया जाएगा। पांच साल में इस योजना पर 6 हजार 600 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस साल 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इंडस्ट्री : 6 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान

मध्यप्रदेश में उद्योग, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। जिनका मुख्य उद्देश्य राज्य को औद्योगिक हब बनाना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके पैदा करना है। इसके लिए बजट में कई अहम घोषणाएं की गई हैं।

गरीब कल्याण : 15 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा

- **संबल योजना-** मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल 2.0) योजना के माध्यम से असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
- **आवास सुविधा-** गरीबों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी एवं ग्रामीण) के लिए कुल 4,500 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
- **खाद्य सुरक्षा-** मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के तहत गरीब परिवारों को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 1,200 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है।
- **स्वास्थ्य सुरक्षा-** आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत प्रदेश के गरीब परिवारों को ?5 लाख तक का निःशुल्क उपचार सुनिश्चित करने के लिए 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
- **कौशल एवं स्वरोजगार-** गरीब युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना और डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के तहत रियायती ऋण और अनुदान का विस्तार किया गया है।

युवा शक्ति: 50 हजार पदों पर सरकारी भर्ती

वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने भाषण में साफ किया कि इस बजट का मूल उद्देश्य राज्य के हर हाथ को काम देना और रोजगार के नए अवसरों को सृजित करना है। इस बार बजट में 50 हजार सरकारी पदों पर भर्ती का ऐलान किया गया है। पुलिस विभाग में अगले 3 साल में 22 हजार 500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस साल 7500 पदों पर भर्ती करने की योजना है। साथ ही प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए 15,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू होगी। आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों के लिए 4,485 शिक्षक भर्ती किए जाएंगे।

कौशल विकास और औद्योगिक प्रोत्साहन

प्रदेश में औद्योगिक और आईटी पार्क विकसित करने के लिए 19,300 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है। साथ ही युवाओं को रोजगार के नए अवसरों से जोड़ने के लिए कौशल विकास का एक विशेष रोडमैप तैयार किया गया है।

जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों की 19,000 महिलाओं को कौशल विकास और आजीविका कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा।

अन्नदाता: किसानों पर खर्च होंगे 1.15 लाख करोड़

सरकार ने इस वर्ष को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का ऐलान किया है। इसे देखते हुए किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं।

- **किसान सम्मान निधि-** प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को मिलाकर किसानों को हर साल कुल 12 हजार रुपए नकद दिए जाते हैं। ये इस बार भी जारी रहेगा।
- **कृषि लोन-** किसानों को वित्तीय सहायता देने के लिए 25 हजार करोड़ रुपए के लोन बांटने का टारगेट तय किया गया है।
- **प्रोत्साहन राशि-** किसानों को विभिन्न मदों में 337 करोड़ की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है।
- **सिंचाई क्षमता का विस्तार-** वित्तीय वर्ष 2026-27 में सिंचाई क्षमता को 7.5 लाख हेक्टेयर बढ़ाने का लक्ष्य है। इसके लिए जल संसाधन और नर्मदा घाटी विकास योजनाओं के लिए बजट में भारी वृद्धि की गई है।
- **सोलर पंप-** किसानों को सिंचाई के लिए आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 3,000 करोड़ रुपए की लागत से एक लाख सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे।
- **कृषि अधोसंरचना-** नहरों के विस्तार, ग्रामीण सड़कों और भंडारण केंद्रों को मजबूत करने के लिए बड़े निवेश का प्रावधान है।
- **फूड प्रोसेसिंग यूनिट-** प्रत्येक जिले में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने की योजना है ताकि किसानों को उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिल सके।
- **पशुपालन और डेयरी-** पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मध्यप्रदेश को दूध की राजधानी बनाने के लक्ष्य के साथ इस क्षेत्र के लिए 2,364 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही 3,000 गौशालाओं के आधुनिकीकरण के लिए नई नीति बनाई गई है।
- **प्राकृतिक खेती-** जैविक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए 21.42 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को पंजीकृत किया गया है।

औद्योगिक अधोसंरचना और पार्क

- **भूमि बैंक का विस्तार-** उद्योगों की स्थापना के लिए प्रदेश में 19,300 एकड़ अतिरिक्त भूमि आरक्षित की गई है ताकि नए निवेश के लिए जमीन की कमी न हो।
- **आईटी और डेटा सेंटर-** इंदौर और भोपाल में नए आईटी पार्क और डेटा सेंटर क्लस्टर विकसित करने के लिए विशेष फंड का प्रावधान किया गया है।
- **प्लग एंड प्ले सुविधाएं-** छोटे उद्योगों के लिए 'प्लग एंड प्ले' बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा, जिससे वे तुरंत अपना काम शुरू कर सकें।

निवेश प्रोत्साहन और नीतियां

- **प्रोत्साहन सहायता-** औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन योजनाओं के तहत 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है।
- **नई औद्योगिक नीति-** सरकार विजन 2030 के अनुरूप एक नई औद्योगिक संवर्धन नीति लागू कर रही है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया है।
- **निवेश प्रस्ताव-** पिछले दो साल में प्राप्त 33 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम को और अधिक सशक्त बनाया गया है।

एमएसएमई और स्टार्टअप्स

- **MSME सहायता-** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण पर ब्याज सब्सिडी और तकनीकी उन्नयन के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य है।
- **स्टार्टअप इकोसिस्टम-** युवाओं के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 'स्टार्टअप हब' और इन्क्यूबेशन सेंटर्स के विस्तार हेतु बजट में विशेष प्रावधान किया गया है।

सिंहस्थ के लिए 3 हजार करोड़

बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर इस साल 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने का अनुमान है।

छात्रवृत्ति के लिए 813 करोड़ रुपये

पीएम जन मन आवास के लिए 900 करोड़ क्षतिग्रस्त पोलो के पुनर्निर्माण के लिए 900 करोड़ रुपये। 11वीं 12वीं और कॉलेज विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिए 813 करोड़ रुपये। आयुष्मान भारत के लिए 863 करोड़ रुपये। मुख्यमंत्री मंजीरा ओला सड़क योजना के अंतर्गत 800 करोड़ रुपये। भारतीयों के लिए 766 करोड़ रुपये। वेदांत पीठ की स्थापना के अंतर्गत 750 करोड़ रुपये। मेधावी विद्यार्थी योजना के लिए 750 करोड़ रुपये और मेट्रो रेल के लिए 650 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री मंजरा टोला योजना 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

सड़क एवं परिवहन

- **ग्रामीण कनेक्टिविटी-** मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना और अन्य ग्रामीण सड़कों के विस्तार के लिए 21,630 करोड़ रुपए के कार्यों को स्वीकृति दी गई है।
- **शहरी मार्ग-** शहरों में सड़कों के रखरखाव और नए निर्माण के लिए 12,690 करोड़ रुपए का प्रावधान है।
- **मेट्रो रेल-** भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल सेवाओं के विस्तार और संचालन को गति दी जा रही है।
- **इंदौर-उज्जैन रोड-** सिक्स लेन वाले इंदौर-उज्जैन हाईवे के निर्माण के लिए 13,851 करोड़ रुपए के बड़े पैकेज का हिस्सा आवंटित किया गया है।

शहरी विकास एवं आवास

- शहरों का आधुनिकीकरण- शहरों के विकास के लिए कुल 21,562 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
- श्रद्धा नगर योजना- वार्ड स्तर पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है।
- प्रधानमंत्री आवास योजना- गरीबों के लिए पक्के घरों के निर्माण हेतु बजट में 6,850 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिसमें अगले 5 साल में 10 लाख नए घर बनाने का लक्ष्य है।

मेधावी छात्र पुरस्कार, साइकिल प्रदाय योजना चलती रहेगी

मोहन यादव कैबिनेट ने 5 सालों के लिए योजनाएं जारी रखने के प्रस्तावों को दी मंजूरी

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक हुई। जिसमें यह निर्णय लिया है कि प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख योजनाएं अगले पांच वर्षों तक निरंतर संचालित की जाएंगी। इसके लिए कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट को मंजूरी देने के साथ वर्ष 2030-31 तक साइकिल प्रदाय, मेधावी छात्र पुरस्कार और छात्रावासों के लिए एक्सीलेंस पुरस्कार योजना को जारी रखने का फैसला लिया गया है।

कैबिनेट ने क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, निर्देशन एवं प्रशासन योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इकाइयां तथा जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजनाएं (संचालनालय) को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतर संचालित रखने का निर्णय लिया। इसके लिए 52 करोड़ 75 लाख रुपए (राजस्व) एवं 1 करोड़ 12 लाख रुपए (पूंजीगत) सहित कुल 53 करोड़ 97 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई।

अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति बस्तियों के विकास, 1032 कार्यालय भवनों के निर्माण, विद्युतिकरण, टंट्या भील मंदिर के जीर्णोद्धार

तथा शिक्षा उपकर से ग्रामीण शालाओं के उन्नयन एवं संधारण कार्यों को भी 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखा जाएगा। इसके लिए 101 करोड़ 75 लाख रुपए (राजस्व) एवं 482 करोड़ रुपए (पूंजीगत) सहित कुल 583 करोड़ 75 लाख रुपए का अनुमोदन किया है।

इसके साथ ही 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालयीन पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को भी 2026-27 से 2030-31 तक चालू रखने पर सहमति बनी। इसके लिए 4,230 करोड़ 82 लाख रुपये (राजस्व) का वित्तीय प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के संचालन के लिए कुल 847 करोड़ 89 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है, जिसमें 498 करोड़ 90 लाख रुपए पूंजीगत मद एवं 348 करोड़ 99 लाख रुपये राजस्व मद के अंतर्गत शामिल हैं।

2030-31 तक वित्तीय निरंतरता को मंजूरी दी

कैबिनेट ने शैक्षणिक संस्थाओं, आश्रमों एवं छात्रावासों के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार, साइकिल वितरण, वन्या प्रकाशन, सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, विद्यार्थी कल्याण, अनुसूचित जनजाति संस्कृति का संरक्षण एवं विकास, देवस्थान, नेतृत्व विकास, भारत दर्शन तथा जनजातीय युवाओं को रोजगारमूलक आर्थिक सहायता योजनाओं को 2026-27 से 2030-31 तक संचालित रखने के लिए 519 करोड़ 50 लाख रुपए की वित्तीय निरंतरता को मंजूरी दी। विशेष पिछड़े अनुसूचित जनजाति समूह अभिकरण, कोल जनजाति विकास अभिकरण, राज्यों को प्रशासनिक लागत तथा विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण से संबंधित योजनाओं के संचालन के लिए 59 करोड़ 6 लाख रुपए (राजस्व) की स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 9वीं एवं 10वीं) को भी वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 690 करोड़ 69 लाख रुपए (राजस्व) के वित्तीय प्रावधान को कैबिनेट ने अनुमोदित किया है।

जेपी अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग

ओपीडी ब्लॉक में भरा धुआं, मरीजों और परिजनों में मची अफरा-तफरी, सर्जिकल सामान जला

भोपाल (नप्र)। भोपाल के जेपी अस्पताल में बुधवार दोपहर अचानक आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। घटना दोपहर करीब 12:15 बजे ओपीडी ब्लॉक के पहले फ्लोर पर हुई, जिस कमरे में आग लगी, वहां सिरिंज, सैंपल कलेक्टिंग उपकरण और अन्य सर्जिकल सामान रखा हुआ था।

कर्मचारियों के अनुसार, पहले कमरे से धुआं उठता दिखाई दिया, जो कुछ ही मिनटों में आग में बदल गया। देखते ही देखते पूरा ओपीडी ब्लॉक धुएं से भर गया और मरीजों व परिजनों में घबराहट फैल गई।

गार्ड ने ताला तोड़कर बुझाई आग, तबीयत बिगड़ी- गार्ड हरिदेव यादव के अनुसार, 12:15 बजे आग की सूचना मिली। जिस कमरे में आग लगी वो फिलहाल स्टोर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। कमरे के अंदर से धुआं निकल रहा था, लेकिन गेट पर ताला लगा हुआ था और चाबी ढूंढने में समय लग रहा था।

ऐसे में गेट तोड़कर अंदर गया और फायर एक्सटिंग्विशर की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया। करीब 8 कंटेनर से आग बुझ पाई। फायर ब्रिगेड आधे घंटे बाद आई, तब तक इंतजार करते तो आग पूरे में फैल सकती थी।

गार्ड यादव ने आगे बताया कि आग बुझाने के बाद उसे बेहोशी सी महसूस हो रही थी। धुआं अंदर पहुंचने से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। ऐसे में उसे तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट दी गई। अब उसकी स्थिति पहले से बेहतर है लेकिन पेट में जलन और आंख बार-बार बंद होने की समस्या बनी हुई है।

काला धुआं पूरे परिसर में फैल गया- प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक धुआं निकलने पर कर्मचारियों ने तुरंत सतर्कता दिखाई। कुछ ही देर में आग की लपटें दिखाई देने लगीं। प्लास्टिक और सर्जिकल सामग्री जलने से काला धुआं पूरे परिसर में फैल गया। ओपीडी में मौजूद मरीजों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। अस्पताल प्रबंधन ने एहतियात के तौर पर तुरंत बिजली सप्लाई बंद कर दी।

30 मिनट देर से पहुंची फायर ब्रिगेड

अस्पताल प्रशासन ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। करीब 30 मिनट में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। हालांकि, तब तक आग पर काबू पा लिया गया था। समय रहते आग बुझा लेने से बड़ा हादसा टल गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

पुरानी वायरिंग और कमजोर प्लानिंग भी घटना एक वजह

प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जिस वायरिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके पास ही सर्जिकल और प्लास्टिक सामग्री रखी थी, जिससे आग तेजी से फैल गई। अस्पताल की पुरानी वायरिंग और कमजोर प्लानिंग को भी घटना की एक वजह माना जा रहा है। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थानों पर नियमित विद्युत निरीक्षण और अग्नि सुरक्षा उपायों की सख्त जरूरत है।

भोपाल में अनुराग बसु, हुमा कुरैशी समेत दिग्गजों का जमावड़ा

2 दिन तक चलेगा 'भोपाल फिल्म फेस्टिवल', कई फिल्मों की होगी स्क्रीनिंग

भोपाल (नप्र)। राजधानी में 21 और 22 फरवरी 2026 को मिंटो हॉल में आयोजित होने जा रहे 'भोपाल फिल्म फेस्टिवल' में देश के चर्चित फिल्मकारों और कलाकारों का जमावड़ा लगेगा। दो दिवसीय इस आयोजन में बेहतरीन सिनेमा के साथ सार्थक संवाद और सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी।

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक हंसल मेहता जूरी सदस्य के रूप में शामिल होंगे। विशेष अतिथि के तौर पर अनुराग बसु अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। वहीं 'कठल' के निर्देशक और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता यशोवर्धन मिश्रा भी निर्णायक मंडल का हिस्सा रहेंगे।

कलाकार और इंडस्ट्री लीडर्स भी होंगे शामिल- फेस्टिवल की क्लोजिंग फिल्म Jugnuma: The Fable (जुगनुमाः द फेबल) होगी, जिसका निर्देशन राम रेड्डी ने किया है। फिल्म में मनोज बाजपेयी, तिलोत्तमा शोम, प्रियंका बोस और दीपक डोबरियाल प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे।

इसके अलावा The Astronaut and His Parrot (द एस्ट्रोनॉट एंड हिज पैरट) में अली फज़ल मुख्य भूमिका में हैं और इसका निर्देशन आरती कड़व ने किया है।

फिल्म Kiss (किस) में आदर्श

गौरव) और स्वानंद किरकिरे नजर आएंगे। इसका निर्देशन वरुण ग्रोवर ने किया है। फ्रांसीसी निर्देशक François Truffaut (फ्रांस्वा त्रुफो) की क्लासिक फिल्म Small Change (स्मॉल चेंज) का प्रदर्शन भी किया जाएगा। इसके अलावा चार श्रेणियों में 32 प्रतियोगी लघु फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी।

पास 129 रुपए में उपलब्ध होगा - सिंगल डे पास 129 रुपए में उपलब्ध रहेगा। इसमें उस दिन की सभी फिल्में, पैनल चर्चा, प्रश्नोत्तर सत्र और कार्निवल शामिल हैं। दोनों दिनों के लिए फेस्टिव पास 199 रुपए में उपलब्ध है।

कटनी में स्कूल दीवार गिरी, 5वीं के छात्र की मौत

परिजन बोले- एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, 500 रुपए में ऑटो से ले गए अस्पताल

कटनी (नप्र)। कटनी जिले के विजयराघवगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कैमोर थाना अंतर्गत बमहनगवां शासकीय स्कूल में बुधवार को हादसा हो गया। स्कूल परिसर की जर्जर दीवार ढहने से कक्षा 5वीं के 11 वर्षीय छात्र राजकुमार बर्मन की मलबे में दबकर मौत हो गई।

मृतक के चाचा सत्यम ने बताया कि उनका भतीजा राजकुमार बर्मन रोज की तरह आज भी स्कूल गया था। इसी दौरान वह विद्यालय परिसर में बने शौचालय का उपयोग करने गया, तभी जर्जर हो चुकी बाथरूम की दीवार उसके ऊपर गिर गई।

बहन ने बचाने की कोशिश की- दीवार गिरने की आवाज सुनकर उसकी नौ वर्षीय बहन मौके पर पहुंची और मलबे में दबे अपने भाई को निकालने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। इसके बाद उसने घटना की जानकारी शिक्षकों और अपने परिजन को दी। सूचना मिलते ही शिक्षक और परिजन मौके पर पहुंचे और मलबे को हटाकर छात्र को बाहर निकाला।

एम्बुलेंस नहीं पहुंची, रिक्शा से ले गए अस्पताल

घटना की जानकारी एम्बुलेंस को दी थी, लेकिन वह समय पर नहीं पहुंची।

इसके बाद 500 रुपए में ऑटो रिक्शा बुक करके वे उसे विजयराघवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने राजकुमार को मृत घोषित कर दिया।

शिकायत पर भी नहीं कराया गया सुधार कार्य

मृतक के परिजन मोहित बर्मन और सत्यम बर्मन सहित अन्य लोगों का आरोप है कि विद्यालय के खंडहर हो चुके शौचालय और भवनों के सुधार कार्य के लिए कई बार शिक्षकों को मौखिक रूप से अवगत कराया गया था, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। इसी लापरवाही का खामियाजा आज छात्र राजकुमार को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा।

डॉक्टर ने महिला से रेप किया

होटल रूम में महिला को नशीला पदार्थ देकर की वारदात, ग्वालियर का रहने वाला है आरोपी

भोपाल (नप्र)। भोपाल के एमपी नगर में स्थित एक होटल रूम में एक डॉक्टर ने महिला को नशीला पदार्थ देकर उसके साथ रेप किया। आरोपी ग्वालियर का रहने वाला है। पीड़िता को इलाज के बहाने भोपाल लाया था। घटना के तीन दिन बाद महिला एमपी नगर थाने पहुंची तथा रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है।

पुलिस के मुताबिक 30 वर्षीय महिला ग्वालियर की रहने वाली है। ग्वालियर के डॉक्टर अमरीश सेंगर से 7 महीने पहले उसने अपना इलाज कराना शुरू किया। इलाज के बाद चर्म रोग और फैलने लगा तो डॉक्टर ने कहा आगे के इलाज के लिए हमें भोपाल जाकर विशेषज्ञ डॉक्टर को दिखाना होगा तथा कुछ टेस्ट भी कराने होंगे। यह टेस्ट ग्वालियर में कहीं भी नहीं होते हैं। 14 फरवरी को डॉक्टर और महिला मरीज भोपाल पहुंचे तथा एमपी नगर जोन टू स्थित एक होटल में ठहर गए।

अस्पताल ले जाने के बजाए होटल ले गया

महिला को शक हुआ तो उसने अपने पति को फोन कर कहा कि डॉक्टर अस्पताल ले जाने के बजाए होटल में लेकर आ गए हैं। मुझे डॉक्टर की नीयत पर भरोसा नहीं हो रहा। यह सुनने के बाद पति ग्वालियर से भोपाल के लिए निकल गया। इधर रात हो जाने पर महिला ने डॉक्टर से कहा कि होटल में कमरे ले लो तो उसने कहा कि होटल में कमरे खाली नहीं है। रात में खाना खाने के बाद अंबरीश ने चर्म रोग की दवा के साथ नशीला पदार्थ दिया।

महिला के बेसुध होते ही की ज्यादती

महिला जब बेसुध हो गई तो अमरीश ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। सुबह पति पहुंच गया बदनामी के डर से उस दिन उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। ग्वालियर पहुंचने के बाद आरोपी जब इलाज के बहाने फिर से संपर्क करने की कोशिश की तो महिला अपने पति को लेकर भोपाल आई तथा यहां पर एमपी नगर थाने में शिकायत दर्ज करा दी। पुलिस ने डॉक्टर अमरीश के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

2 सिस्टम के असर से एमपी में बदलेगा मौसम

रतलाम , इंदौर-ग्वालियर,उज्जैन-गुना समेत 22 जिलों में बारिश का अलर्ट

भोपाल (नप्र)। मध्य प्रदेश के 22 जिलों में बुधवार को आंधी, बारिश और गरज-चमक का अलर्ट है। इनमें इंदौर, ग्वालियर-उज्जैन भी शामिल हैं। रतलाम जिले के अलग-अलग इलाकों में मंगलवार रात बारिश हुई है। 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवात) और एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) की वजह से मौसम बदलेगा। गुरुवार को भी ग्वालियर-चंबल में बारिश होने का अनुमान है।

बुधवार को जिन जिलों में बारिश होने के आसार हैं, उनमें इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, धार, आलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, शाजापुर, राजगढ़, आगर-मालवा, नीमच, मंदसौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर शामिल हैं। भोपाल, बड़वानी, खरगोन, देवास, सीहोर,

विदिशा, सागर, दमोह, पन्ना और सतना में बादल छाए रह सकते हैं। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया कि दो साइक्लोनिक सर्कुलेशन और वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से मौसम बदलेगा। बुधवार को ज्यादा जिलों में असर देखने को मिलेगा। इस वजह से न्यूनतम तापमान में फिलहाल बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

गुरुवार को भी दिखेगा सिस्टम का असर- मौसम विभाग की मानें तो गुरुवार को भी सिस्टम का असर देखने को मिलेगा। ग्वालियर, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद सिस्टम कमजोर होगा। इस वजह से कहीं भी बारिश या गरज-चमक का अलर्ट नहीं है।

ट्रक ने बाइक सवारों को रौंदा...एक की मौत

गुना में 4 लोगों को 30 मीटर तक घसीटा, पहिया ऊपर से निकला, 3 की हालत गंभीर

गुना (नप्र)। गुना के कुशमोदा इलाके में बुधवार को तेज रफ्तार ट्रक ने तीन बाइक सवारों को कुचल दिया। ट्रक बाइक सवारों को करीब 30 मीटर तक घसीटता ले गया।

ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि तीन की हालत गंभीर है। टक्कर मारने के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है।

मक्का लोड ट्रक माल गोदाम की तरफ जा रहा था- जानकारी के अनुसार घटना बुधवार सुबह करीब 11:30 बजे की है। चिंताहरण की ओर से मक्का लोड ट्रक शहर की तरफ आ रहा था। वह माल गोदाम तरफ जा रहा था। इसी दौरान कुशमोदा के पास ट्रक ने ओवरटेक करते समय एक-एक कर तीन बाइक को पीछे से टक्कर मार दी।

हादसे में कैलाश बाबू धाकड़ और उनके पिता दौलतराम धाकड़ घायल हो गए। कैलाश अपने पिता का इलाज कराने के लिए उदयपुरी से गुना आ रहे थे। वहीं एक्टिवा सवार राजकुमारी सिसोदिया को भी चोटें आई हैं। वह अपने पति के साथ राघौगढ़ से गुना आ रही थीं।

युवक के शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह अलग- हादसे का शिकार बाइक सवार ट्रक के नीचे ही फंस गया। ट्रक बाइक को लगभग 30 मीटर तक घसीटते ले गया। हादसे में बाइक सवार शिवनंदन शर्मा (28) निवासी सुहाय की मौके पर ही मौत हो गई। उसके शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह अलग हो गया। दोनों पैर कट गए। ट्रक का पहिया उसके ऊपर से निकल गया था।

पुलिस को ट्रक बजरंगगढ़ बायपास पर खड़ा मिला- कैंट टीआई अनूप भार्गव ने बताया कि हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर भाग निकला। हालांकि, पुलिस को ट्रक बजरंगगढ़ बायपास पर खड़ा मिला। ड्राइवर नदारद था।

कूनो में बढ़ा चीतों का परिवार...गामिनी दूसरी

तीन शावकों का हुआ जन्म, भारत में चीतों का कुनबा बढ़कर हुआ 38

श्योपुर (नप्र)। कूनो नेशनल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से लाई गई चीता गामिनी ने 18 फरवरी को तीन स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है। यह खुशखबरी दक्षिण अफ्रीकी चीतों के भारत आगमन के तीन वर्ष पूरे होने के दिन सामने आई। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी जानकारी दी। मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस उपलब्धि को भारत के ऐतिहासिक संरक्षण अभियान की बड़ी सफलता बताया। उन्होंने कहा कि यह 'प्रोजेक्ट चीता' के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

दूसरी बार दिया शावकों को जन्म

गामिनी दूसरी बार मां बनी है। यह भारतीय धरती पर चीतों का नौवां सफल कुनबा है। इन नए शावकों के जन्म के साथ भारत में जन्मे जीवित शावकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। अब देश में कुल चीता आबादी 38 तक पहुंच गई है।

अधिकारियों के अनुसार, प्रत्येक नया जन्म 'प्रोजेक्ट चीता' को मजबूती प्रदान कर रहा है। फील्ड स्टाफ और पशु चिकित्सकों की निगरानी और समर्पण से यह सपना साकार हो रहा है, जो चीता पुनरुद्धार परियोजना की सफलता के लिए अहम है।

सीएम ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

भारत में पैदा हुए शावकों की संख्या बढ़कर 27 हो गई है और कुल चीतों की आबादी 38 हो गई है। सीएम ने कहा कि गामिनी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। पार्क में चीतों के आने के बाद से नौवां सफल प्रसव है।

शादी में डांस करते-करते आया हार्ट अटैक

खरगोन में मेहंदी की रस्म में दूल्हे के मामा की मौत, पत्नी के साथ नाच रहे थे

खरगोन/बड़वानी (नप्र)। खरगोन में मेहंदी की रस्म के दौरान दूल्हे के मामा को हार्ट अटैक आ गया। वे नाचते-नाचते जमीन पर गिर पड़े। परिजन ने इसे उनका डांस स्टेप ही समझा। कुछ देर तक जब वे नहीं उठे तो रिश्तेदार उनकी तरफ बढ़े।

उन्हें निढाल देखकर अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टर ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी। मामला खरगोन के वझरा गांव का है। इसका वीडियो भी सामने आया है।

बड़वानी में पिपलुद गांव के रहने वाले घनश्याम यादव (40) अपने भांजे की शादी में वझरा आए थे। मंगलवार रात को मेहंदी की रस्म थी। इस दौरान घनश्याम अपनी पत्नी के साथ नाच रहे थे। परिवार के अन्य सदस्य भी जश्न में शामिल थे।

8वीं क्लास में पढ़ता है इकलौता बेटा

घनश्याम यादव पेशे से किसान थे। करीब आठ एकड़ जमीन है। उनके साथ उनकी पत्नी और इकलौता बेटा भोला यादव भी मौजूद थे। भोला 8वीं क्लास में पढ़ता है।

वे भांजे अंकित और भांजी रजनी की शादियों में भात लेकर मंगलवार को ही वझरा पहुंचे थे। शाम को मेहंदी के साथ ही संगीत भी रखा गया था।